₹ 20
www.kewalsach.com
निर्भीकता हमारी पहचान
मई 2025

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PS-35

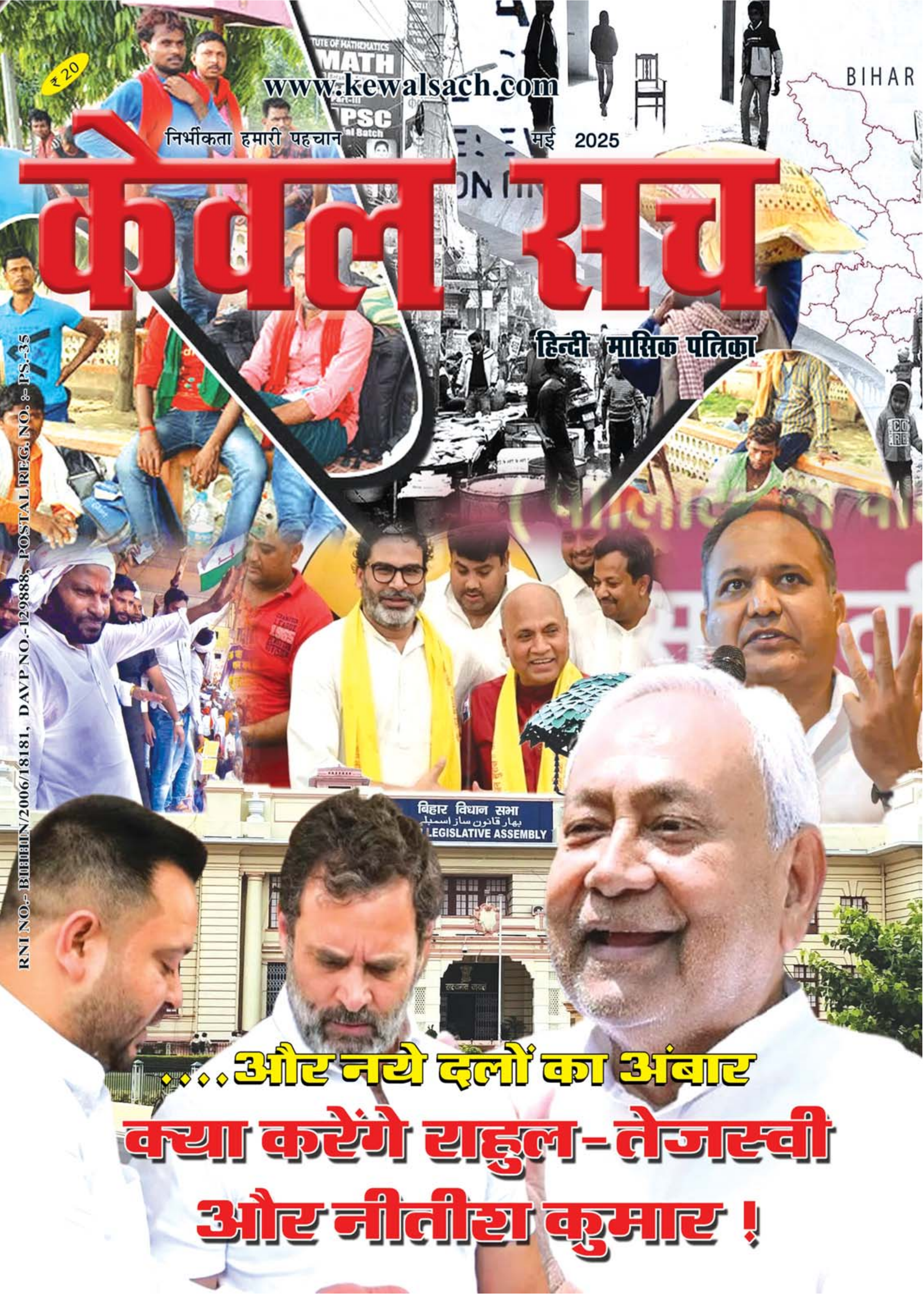

...और नये दलों का अंबार

क्या करेंगे राहुल-तेजस्वी और नीतीश कुमार !

जन-जन की आवाज है केवल सच

केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
Kewalsach news
Mob.: 9431073769, 9308815605
खबर वहीं, जो केवल सच हो

केवल सच TIMES
21 तक आने की संभावना नहीं: विज्ञान मंत्रालय

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM UPI
G Pay पे Paytm

www.kewalsach.com www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

एस.एन. कृष्णान
01 मई 1932

अनुष्का शर्मा
01 मई 1988

अशोक गहलोत
03 मई 1951

उमा भारती
03 मई 1959

तृष्णा कृष्णान
04 मई 1983

सनी लियोनी
13 मई 1981

जरीन खान
14 मई 1980

माधुरी दिक्षित
15 मई 1967

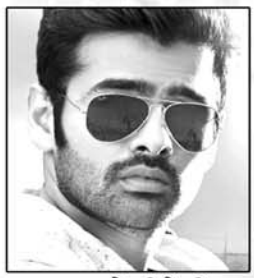
राम पेथीनेनी
15 मई 1988

सोनल चौहान
16 मई 1987

स्व.पंकज उदास
17 मई 1951

चार्मी कौर
17 मई 1987

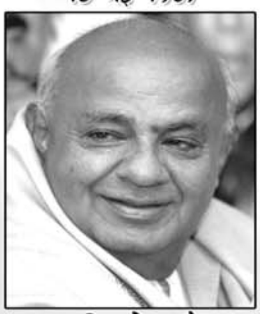
एच.डी. देवगौड़ा
18 मई 1933

एनटीआर जूनियर
20 मई 1983

महबूबा मुफ्ती
22 मई 1959

करण जोहर
25 मई 1972

नितिन गडकरी
27 मई 1957

रवि शास्त्री
27 मई 1962

पंकज कपूर
29 मई 1954

परेश रावल
30 मई 1950

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

सेना का ऑपरेशन सिन्दूर

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

मौत का बदला मौत से 07 मई 2025 को भारतीय सेना ने ले लिया है। 26 लोगों को धर्म पूछकर पुरूषों को गोलियों से भून डालकर महिलाओं की सुहाग को उजाड़ दिया था ''**ऑपरेशन सिन्दूर**'' उसी सिंदूर का बदला है, जिसे सुहाग के खून से धोने की कोशिश की गई थी **ऑपरेशन सिंदूर** पहलगाम हमले में मारे गए उन 26 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि है, जो आतंक की कायराना हरकत का शिकार बने थे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का एक नाम है। भारत ने कहा कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढाँचे को निशाना बनाना था। इतिहास साक्षी है कि भारत देश ने अकेले 1971 की लड़ाई में अमेरिका के समर्थन नहीं होने के बावजूद पाकिस्तान को हराया था। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिका समेत यूरोप देशों ने प्रतिबंध लगा दिए, फिर भी भारत अपने लक्ष्य पर डटा रहा। देश ने अपने दम पर ही 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, वो भी बिना वैश्विक समर्थन के और अब 2025 में भी बिना दुनिया के समर्थन के पाकिस्तान को पैदल कर दिया। रूस के पुतिन ने भारत का साथ दिया और रूस ने बिना शर्त अपनी मित्रता निभाई है। पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और 26 पर्यटकों की क्रूर हत्या की निंदा की लेकिन अमेरिका सदैव व्यापार और खुद को सुपर पावर समझकर भारत को कमजोर करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद को अप्रत्यक्ष सहयोग करने का खेल भी अमेरिका सदियों से करता आ रहा है जब अमेरिका में आतंकवाद का दहशत देखा तब से भारत का समर्थन करता है लेकिन उसमें भी अपना लाभ ही देखता है। भारत देश को अकेले आगे बढ़ने की नीति पर चलनी होगी। डिफेंस को और मजबूत करना होगा, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा और एक ताकत के तौर पर उभरना होगा, ताकि भविष्य में किसी के समर्थन का मोहताज तक नहीं होना पड़े। धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादियों को भारत से और नफरत बढ़ गया है और देश के भीतर की दोगली राजनीति की वजह से पाकिस्तान के पक्ष में गोलबंद होकर सेना के जवानों का मनोबल गिराते हैं तथा केन्द्र की सरकार को भी टारगेट करते हैं। जम्मू और कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम नरसंहार की प्रतिक्रिया में किए गए ''**ऑपरेशन सिन्दूर**'' से मोदी की साख मजबूत हुई लेकिन अमेरिका के दवाब के कारण भारत का तेवर कमजोर पड़ गया। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन ''**प्रतिरोध मोर्चा**'' ने ली। पहलगांव में मारे गए लोग हिन्दू पर्यटक थे, जिनमें 26 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। यह पहली दफा था जब धर्म पूछा गया और महिलाओं को कहा गया कि जाकर मोदी को बोल देना। 1947 में धर्म के नाम पर बंटा पाकिस्तान देश की कूटनीति की वजह से हमलावरों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनके नाम और धर्म पूछे थे, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था। पुरुषों के कपड़े उतरवाए गए तथा उनका खतना तक देखा गया, जिन पुरुषों का खतना नहीं था, उन्हें उनके परिवार के सामने हिन्दू होने कारण गोली मार दिया गया। भारत ने पाकिस्तान पर हमलावरों का समर्थन करने का आरोप लगाया, हालांकि पाकिस्तान ने आरोपों से साफ इनकार किया। कश्मीर विवाद, जो 1947 से जारी है, इस विवादित क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों और झड़पों को बढ़ावा दिया है। 22 अप्रैल 2025 को, भारतीय प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में एक हमले में 26 नागरिक मारे गए और इसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के एक सहयोगी संगठन, प्रतिरोध मोर्चा ने लेकर भारत को अशांत रखने का माहौल बना दिया। **ऑपरेशन सिंदूर** के दौरान अमेरिका से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन, रूस या जापान, जिनके साथ भारत के काफी अच्छे संबंध हैं, उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने आतंक के खिलाफ भारत के ''**ऑपरेशन सिन्दूर**'' का विरोध नहीं किया, इसे ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। आतंकी हमले में मारे गये हिन्दुओं पर संवेदना तो कई देशों ने किया लेकिन आपरेशन सिन्दूर से सबने दुरी बनायी और ऑपरेशन सिन्दूर की शुरूआत ने मोदी देश के विपक्ष में भी साख मजबूत की लेकिन अमेरिका के दवाब पर ''**ऑपरेशन सिन्दूर**'' का विराम लगने से मोदी एवं शाह की प्रतिष्ठा धूमिल होती दिख रही है। आतंकी हमले का भी राजनीतिकरण करना देशवासियों को खटक रहा है। सिन्दूर की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती जैसी हजारों नारियों ने अपनी कुर्बानी दी है लेकिन **ऑपरेशन सिन्दूर** नाम देकर जितनी प्रशंसा बटोरी गयी उससे ज्यादा जगहसाई भी हो रही है। सेना के जवानों का मनोबल राजनीति लाभ के लिए तोड़ा जाना काफी चिंताजनक है।

आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारना और देश की बेटियों की मांग की सिन्दूर को उजाड़ने वाले को मुहतोड़ जवाब देने के लिए ''**ऑपरेशन सिन्दूर**'' के नाम से आतंकवादियों से बदला पाकिस्तान में घूंसकर लिया गया। 2019 के चुनाव के वक्त पुलवामा में सैनिकों से भरी बस को बम धमाके से मौत के घाट उतार दिया था लेकिन 'मोदी है तो मुमकिन है' के नारे के साथ पाकिस्तान में घुंसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला लिया गया था। अपनी गंदी हरकतों की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में नंगा हो चुका हैं कि वह आतंकवादियों का गढ़ है और उनको संरक्षण देता है। भारत के प्रति पाकिस्तान की ईर्ष्या इस कदर हावि है की समझौता के बाद भी सीजफायर करके अपने मंसूबे को साबित कर चुका है। भारतीय राजनीति में पक्ष एवं विपक्ष सत्तालोलुप्ता की वजह से अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का हौसला भी बढ़ाता है जबकि इनके परिणाम काफी घातक होते हैं। मुम्बई ब्लास्ट, अक्षरधाम, संसद पर हमला सहित अयोध्या हनुमान गढ़ी के साथ ऐसे कई हादसे हैं जिसमें आतंकवादियों ने भारत को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। ''ऑपरेशन सिन्दूर'' ने भारत की जनता को भी जागृत कर दिया कि भारत का एक-एक बच्चा युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार है लेकिन भारत की दोगली राजनीति को समझ पाना बहुत कठिन है।

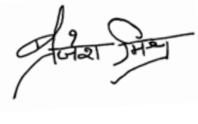

अप्रैल 2025

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

अनिल टाइगर

ब्रजेश जी,

आपकी पत्रिका '**केवल सच**' सही मायने में सरकार एवं प्रशासन का आंख खोलता है। अप्रैल 2025 अंक में राँची ब्यूरो ओम प्रकाश ने ''**पुरानी रंजिश और दस एकड़ जमीन बनी भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या का कारण**'' आलेख में पूरे मामले की सटीक पड़ताल करके खबर को लिखा है। अपराध एवं पुलिस से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को प्राथमिकता से केवल सच स्थान देता है लेकिन राजनीति एवं प्रशासनिक सेवाओं में चल रहे फेरबदल सहित भ्रष्टाचार की जगहों को भी स्थान मिलना चाहिए।

✦ **विजय हाजरा, बूटी मोड़, खेलगांव, राँची**

नवादा एवं भोजपुर

ब्रजेश जी,

बिहार का नवादा जिला का खबर मिथिलेश कुमार एवं मनीष कमलिया ने कई महत्वपूर्ण खबरों को अप्रैल 2025 अंक में स्थान दिया है तो दूसरी ओर भोजपुर के पत्रकार गुड्डू कुमार सिंह ने भी पुलिस एवं अपराध से जुड़ी कई खबरों को प्राथमिकता से पाठकों के समक्ष रखा है। सरकार के पक्ष एवं विपक्ष की समुचित खबरों को केवल सच के पत्रकार उचित स्थान देते हैं। राजनीति एवं भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरों को केवल सच में पढ़कर काफी संतोष प्राप्त होता है। कोर्ट के आदेश की समरक्षा छपे तो बेहतर होगा।

✦ **प्रभुदयाल सक्सेना, गाँधी नगर, नई दिल्ली**

एनकाउंटर

मिश्रा जी,

अपने नाम के अनुरूप खबर लिखने के मामले में केवल सच पत्रिका कभी समझौता नहीं करता। अप्रैल 2025 अंक में अमित कुमार की खबर ''**अपराधियों पर बिहार पुलिस का एनकाउंटर**'' में बिहार में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों का विश्लेषण करते हुए खबर को विस्तार से लिखा गया है। राजनीतिक संरक्षण एवं माननीय के आपराधिक गतिविधियों सहित पुलिस महमके की लाचारी एवं लालची रवैय्या को भी बारीकी से लिखा गया है। कुंदन कृष्णन का बिहार आना अपराधियों के लिए काल बन गया है। बड़ी लेकिन विस्तार से लिखा गया पठनीय खबर है।

✦ **रजत यादव, योगीपुर, पत्रकार नगर, पटना**

बिहार

मिश्रा जी,

मैं केवल सच पत्रिका को नियमित रूप से पढ़ता हूं। ''**आईपीएस बदलेंगे बिहार**'' अप्रैल 2025 अंक के संपादकीय में आपने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर काफी कारगर खबर को लिखा है। आपका संपादकीय काफी सटीक एवं ज्वलंत समस्याओं पर आधारित रहता है तथा सरल भाषा में लिखा जाता है जिसकी वजह से पाठकों को इसके मूल भाव को समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। जितने आईपीएस का नाम आपने लिखा है की किस प्रकार राजनीति में भाग्य आजमना चाहते हैं और उनका हश्र क्या है। केवल सच अपनी बेबाक लेखनी के लिए ही खास पहचान रखता है।

✦ **जी एन मिश्र, डीएसपी (सेवा०) गोरखपुर**

धर्मेन्द्र की खबरें

संपादक जी,

मैं केवल सच, पत्रिका का नियमित पाठक हूं और कवर से बैक पेज तक को पढ़ता हूं। अप्रैल 2025 अंक में ''डीपीएम पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप'', ''जनसुराज सुप्रीमों पहुंचे मुजाहिद आलम के आवास'', ''हत्या के महज 48 घंटे में पुलिस ने किया उद्‌भेदन'' सहित कई खबरें जानकारीप्रद लगे लेकिन किशनगंज की समीक्षात्मक राजनीति एवं भ्रष्टाचार के साथ - साथ जिला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी पर सटीक समीक्षात्मक खबरों को प्रकाशित भी करना चाहिए। जिला के ऐतिहासिक खबरों को भी पूर्ण स्थान मिलना चाहिए।

✦ **मो अरमान, छात्र, ठाकुरगंज, किशनगंज**

यूपी

संपादक जी,

अप्रैल 2025 अंक में प्रकाशित यूपी की खबर में अजय कुमार की खबर ''**तीन साल में यूपी से खत्म हो जाएगी गरीबी-योगी**'' में गंभीर बातों को सही ढ़ंग से लिखा है तो दूसरी खबर संजय सक्सेना की ''**वक्फ संशोधन बिल**'' में मुसलमानों की नाराजगी के विषय को काफी बुनियादी तरीके से लिखा है कि राजनीति का कितना नुकसान सपा एवं भाजपा को होगा का सही समीक्षा किया है। तीसरी खबर संजय सक्सेना की खबर ''विवाद के समय बीजेपी अपने लोगों को छोड़ देती है'' भी चिंतशील है। ऐसी खबरों को प्रथमिकता से प्रकाशित करें।

✦ **रौषन सिंह, बलिया बस स्टैण्ड, उत्तरपद्रेश**

अन्दर के पन्नों में

अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा....83

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, **DAVP No.- 129888**

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 19,	अंकः- 228,	माहः- मई 2025,	मूल्यः- 20/- रू

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र
श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका (एडमिन)	7782053204
सुरजीत तिवारी	9431222619
निलेन्दु कुमार झा	9431810505, 8210878854
सच्चिदानन्द मिश्र	9934899917
रामानंद राय	9905250798
डॉ० शशि कुमार	9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र	9430888060, 8873004350
अमोद कुमार	9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल	9430000482, 9798874154
मनीष कुमार कमलिया	9934964551, 8809888819

उप-संपादक

प्रसुन्न पुष्कर	9430826922, 7004808186
ब्रजेश सहाय	7488696914
ललन कुमार	7979909054, 9334813587
पंकज कुमार सिंह	9693850669, 9430605967

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय	7992210078
संतोष कुमार यादव	8210487516,

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू'	9905244479, 7979075212
राजीव कुमार शुक्ला	9430049782, 7488290565
काशीनाथ गिरी	9905048751, 9431644829
अविनाश कुमार	7992258137, 9430985773
कुमार अनिकेत	9431914317

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह	8210772610, 9431253179
मिथिलेश कुमार	9934021022, 9431410833
नवेन्दु कुमार मिश्र	9570029800, 9199732994
ऋषिकेश पाण्डेय	7488141563, 7323850870

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र	9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा	9386901616, 7762089203

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि	9308454485
रवि कुमार पाण्डेय	9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील	9905101976, 8521711976
आनन्द प्रकाश	9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार	9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव	8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार	9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०) :-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०) :-	गौरव कुमार	9472400626
(ग्रा०) :-	मुकेश कुमार	7004761573
बाढ़ :-		
भोजपुर :-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर :-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर :-		
रोहतास :-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
:-		
गया (श०) :-	सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०) :-		
औरंगाबाद :-		
जहानाबाद :-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल :-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा :-		
:-		
नवादा :-	अमित कुमार	9162664468
:-		
मुंगेर :-		
लखीसराय :-		
शेखपुरा :-		
बेगूसराय :-		
:-		
खगड़िया :-		
समस्तीपुर :-		
जमुई :-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली :-		
:-		
छपरा :-		
सिवान :-		
:-		
गोपालगंज :-		
:-		
मुजफ्फरपुर :- .		
:-		
सीतामढ़ी :-		
शिवहर :-		
बेतिया :-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा :-		
मोतिहारी :-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा :-		
:-		
मधुबनी :-		
:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा :-		
मधेपुरा :-		
सुपौल :-		
किशनगंज :-		
:-		
अररिया :-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया :-		
कटिहार :-		
भागलपुर, :-		
(ग्रा०) :-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया :-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
................................., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय त्तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

................................., स्टेट हेड
सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

....

....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

....

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप	7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र	7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव	9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995, 8409103023

....

संयुक्त संपादक

....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672

....

....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	7903856569
	:- ओम प्रकाश	9708005900
साहेबगंज	:-	
खूँटी	:-	
जमशेदपुर	:- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता	9304824724
हजारीबाग	:-	
जामताड़ा	:-	
दुमका	:-	
देवघर	:-	
धनबाद	:-	
बोकारो	:-	
रामगढ़	:-	
चाईबासा	:-	
कोडरमा	:-	
गिरीडीह	:-	
चतरा	:- धीरज कुमार	9939149331
लातेहार	:-	
गोड्डा	:-	
गुमला	:-	
पलामू	:-	
गढ़वा	:-	
पाकुड़	:-	
सरायकेला	:-	
सिमडेगा	:-	
लोहरदगा	:-	

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं** **'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक "**मगध इंटरनेशनल स्कूल**" टेकारी

" **केवल सच** " पत्रिका **एवं** " **केवल सच टाइम्स** "

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं** **'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि	
महेश चौधरी	9572600789, 9939419319
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सूमन सौरभ	9471492480
शालनी झा	9031374771, 7992437667
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
दीपनारायण सिंह	9934292882,
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
कुमार राजू	9310173983,
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140

छायाकार	
त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
राँची	गुड्डी साव	6299470142, 7992321146
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाईबासा		

कितने अहम हैं छोटे दल, जिनके बिना आसान नहीं किसी भी गठबंधन की राह

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनावी विगुल बज गई है, बस तिथि का शुभ दिन निकलना बाकि है। हांलाकि चुनाव होने में लगभग छः महीने का इंतजार जरूर है किन्तु राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं के बीच अपनी जोर आजमाईस आजमाने में जुट गये हैं। बहरहाल, एनडीए और महागठगंधन के लिए चुनाव से पूर्व नये-नये दलों के उद्गम कही पेरशानी न बन जाये, इसके भी मंथन जारी है। गौरतलब है कि बिहार में किसी दल को सरकार बनाने में छोटे दलों का साथ महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसे में युवा रोजगार और बिहार से पलायन जैसे मुख्य मुद्दे को लेकर छोटी दलों के एजेंडे ने बड़े दलों के बीच समस्या जरूर खड़ी कर दी है। सनद् रहे कि वर्षो से जाति को आधार बनाकर राजनीतिक दलों ने चुनाव में जीत-हार को महत्व दिया था किन्तु 2025 के विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण के साथ-साथ युवा रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हावी दिखेंगे। क्योंकि अभी ताजा-ताजा जन्म ली नई पार्टियां इसे ही आधार बना रही है, चाहे पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे की पार्टी हिन्द सेना हो या प्रशांत किशोर की जन सुराज। एक मुद्दे को अलग-अलग दलें अलग चुनाव लड़कर किसकी कितनी वोटें काटेंगी, इसकी गंभीरता को जदयू, भाजपा, कांग्रेस और राजद बखूबी समझ रही है। इसलिए छोटे दलों के अहमियत को नजरअंदाज करना बड़ी भूल मानी जा सकती है। बहरहाल, दलों के अंबार में क्या करेंगे राहुल-तेजस्वी और नीतीश कुमार। दलों की बढ़ती संख्या से लेकर निशांत की राजनीति में इंट्री के कयास पर प्रस्तुत है संयुक्त संपादक **अमित कुमार** की समीक्षात्मक रिपोर्ट :-

1990 से बिहार की सियासत में कुछ नाम ऐसे हैं, जिनके इर्द-गिर्द यहां की सियासत घूमती रही है। इनमें लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी का नाम शामिल है। रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का सिक्का चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर होगी, यह भी जाहिर है। ज्ञात हो कि बिहार की सियासत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शिष्यों का बोलबाला रहा है। पिछले 35 साल से सूबे की सत्ता जिन लालू यादव और नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द घूमती रही है, यह दोनों दिग्गज भी जेपी के ही शिष्य हैं। बिहार एक बार फिर विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू यादव अपनी सियासी मशाल अपने बेटे तेजस्वी यादव को सौंप चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से पार्टी की कमान संभाल चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भी राजनीति में एंट्री की चर्चाएं बहुत तेज हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल (यूनाइटेड) में भी

नीतीश कुमार

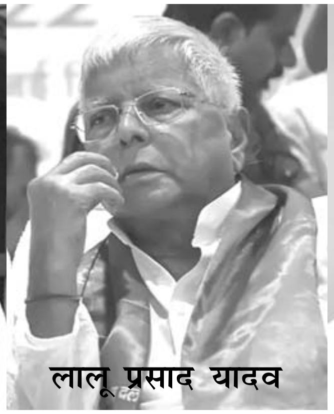

लालू प्रसाद यादव

रामविलास पासवान

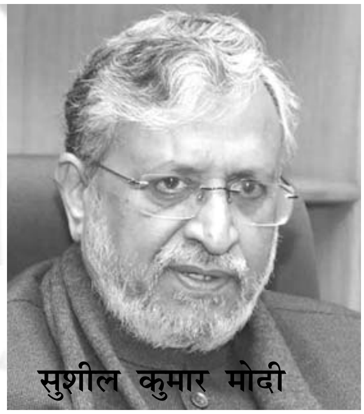

सुशील कुमार मोदी

उनके बेटे निशांत कुमार की लॉन्चिंग की डिमांड जोरों पर है। जेपी के इन दोनों शिष्यों की नई पीढ़ी के साथ ही चर्चा में वो पार्टियां भी हैं, जिनका अभ्युदय पिछले कुछ महीनों में हुआ है।

गौरतलब है कि बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियां मैदान में होंगी। वहीं, दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज समेत कई नई पार्टियां भी चुनाव मैदान में दिग्गज दलों से दो-दो हाथ करती नजर आएंगी। ऐसे दलों की लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की पार्टी 'आप सबकी आवाज' से लेकर शिवदीप वामनराव लांडे की 'हिंद सेना' के भी नाम शामिल हैं। हांलाकि बीते दिनों आरसीपी सिंह ने जन सुराज के कार्यलाय में पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में वह पार्टी में शामिल हुए। इसके साथ ही आरसीपी सिंह की पार्टी 'आसा का भी जन सुराज में विलय हो गया, जिसका गठन अक्टूबर, 2024 में किया गया था। मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य में व्यवस्था बदलाव की मुहिम में शामिल होने के लिए

जयप्रकाश नारायण

आरसीपी सिंह का मैं जन सुराज में स्वागत करता हूं। आरसीपी सिंह ने कहा कि मैंने जन सुराज की विचारधारा से प्रभावित होकर इस पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। वही नई पार्टियों की लिस्ट में सबसे ताजा नाम है कांग्रेस के नेता रहे इंजीनियर आई.पी. गुप्ता की पार्टी इंडियन इंकलाब पार्टी का। सवाल यह है कि इतने विकल्प होने के बाद भी क्या आम आदमी एनडीए और महागठबंधन से इतर वाली सरकार चुनने का साहस कर पाएगा। बिहार की राजनीति में अभी दो खेमे हैं-पहला खेमा एनडीए का है, जिसमें भाजपा, जेडीयू, लोजपा रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम यानी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल हैं। दूसरा खेमा महागठबंधन का है, जिसे व्यापक स्वरूप में हम इंडिया ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल स्थापित है तो कांग्रेस, वामदल और विकासशील इंसान पार्टी का भी नाम शामिल है। इन दोनों खेमों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी पिछले चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीतकर अपना जलवा दिखा चुकी हैं। इनके अलावा कुछ पार्टियां ऐसी हैं, जो हाल ही में अस्तित्व में आई हैं। इनमें सबसे पहला नाम प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी का है। प्रशांत किशोर ने बहुत जोर-शोर से और 2 साल की लंबी पदयात्रा के बाद 2 अक्टूबर, 2024 में जन सुराज पार्टी का गठन किया था। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव, 2025 में सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने 40 सीटों पर महिला

आई.पी. गुप्ता

और इतनी ही सीटों पर मुसलमान प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर रखा है। इसके साथ ही बिहार में बदलाव लाने की बात करने वाले पीके ने जन सुराज की सरकार बनने पर शराबबंदी खत्म करने का वादा किया है। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के नारे के साथ बिहार के सियासी मैदान में उतरी जन सुराज पार्टी का एजेंडा समृद्ध बिहार बनाने, बिहार में बदलाव लाने और नया बिहार बनाना है। जन सुराज रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों के जरिये जाति-वर्ग से परे हटकर गरीब, युवा और बुद्धिजीवी वोटबैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में है। नई पार्टियों की लिस्ट में इंडियन इंकलाब पार्टी का नाम सबसे नया है। कांग्रेस नेता रहे इंजीनियर आई.पी. गुप्ता ने इस पार्टी का गठन किया है। गांधी मैदान में पहले आई.पी. गुप्ता ने पान समाज की महारैली की और इंडियन इंकलाब पार्टी नाम से नया दल बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने बिहार के बड़े नेताओं का जिक्र करते

हुए कहा कि इनकी पार्टियां इसलिए खड़ी हो गईं, क्योंकि इनके पीछे इनका समाज खड़ा हो गया था। आज तांती ततवा भी खड़े हो गए हैं और हमारी इंडियन इंकलाब पार्टी बिहार में चुनाव लड़कर इतिहास रचने का काम करेगी। बताते चले कि अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर आई.पी. गुप्ता ने पटना के गांधी मैदान में पान समाज की महारैली की। इस रैली में जुटी भारी भीड़ के बीच इंजीनियर गुप्ता ने इंडियन इंकलाब पार्टी नाम से अपना दल बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने पान समाज के लोगों को संबोधित करते हुए लालू यादव, नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी, रामविलास पासवान जैसे नेताओं और उनकी पार्टी का जिक्र किया। आईपी गुप्ता ने कहा कि इनकी पार्टियां इसलिए चल सकीं, क्योंकि इनके पीछे सबसे पहले इनकी जमात खड़ी हुई। आज तांती-ततवा भी खड़े हो गए हैं और इंडियन इंकलाब पार्टी भी लड़ेगी, बिहार में इतिहास रचेगी। उन्होंने पान समाज को आरक्षण देकर वापस ले लिए जाने का मुद्दा उठाया। इंडियन इंकलाब पार्टी ने पान समाज को आरक्षण और सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए संघर्ष को अपना एजेंडा बताया है। आई.पी. गुप्ता की कोशिश तांती-ततवा समाज को अपने पक्ष में गोलबंद करने की है। आईपी गुप्ता ने अपने समाज के लिए आरक्षण की मांग भी की है। हालांकि आई.पी. गुप्ता ने आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने या नहीं

उतारने को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया है।

दिलचस्प है कि बिहार का सिंघम नाम से चर्चित शिवदीप लांडे ने भारतीय पुलिस सेवा की नौकरी छोड़ अपनी पार्टी बना ली है। शिवदीप लांडे ने अप्रैल महीने में ही हिंद सेना पार्टी नाम से अपना राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र के अकोला में जन्मे शिवदीप लांडे ने बिहार चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का भी ऐलान कर दिया है और कहा है कि हिंद सेना अपने उम्मीदवार उतारेगी। दबंग अधिकारी के रूप में चर्चित शिवदीप लांडे बिहार में बदलाव लाने को अपना राजनीतिक एजेंडा बताया है। उन्होंने यह भी कहा था कि कई पार्टियों ने मुझे राज्यसभा भेजने, मंत्री-मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव दिए, लेकिन बिहार में बदलाव लाना चाहता हूं और इसलिए नई पार्टी बनाने का

प्रशांत किशोर

शिवदीप वामनराव लांडे

आरसीपी सिंह

पुष्पम प्रिया चौधरी

फैसला किया। बता दें कि शिवदीप लांडे के ससुर विजय शिवतारे महाराष्ट्र की पुरंदर सीट से एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के विधायक हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी शिवदीप लांडे युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं और उनकी पार्टी का फोकस भी इसी युवा वोटबैंक पर है। आईपीएस से राजनेता बने बिहार के सिंघम कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया था। वही बिहार में पीके की जन सुराज के ऐलान से कुछ ही महीने पहले एक नई पार्टी अस्तित्व में आई थी- आप सबकी आवाज। आप सबकी आवाज पार्टी का गठन पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने किया था। आरसीपी सिंह की गिनती कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में होती थी। वह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया था। जेडीयू के बाद आरसीपी बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में लौट आने के बाद पार्टी छोड़ दी थी। आरसीपी सिंह कुर्मी समाज से आते हैं, जिसे जेडीयू के लव-कुश समीकरण का आधार माना जाता है। आप सबकी आवाज पार्टी का फोकस भी कुर्मी वोटबैंक पर ही माना जा रहा है। वही आरसीपी की पार्टी ने एनडीए या महागठबंधन में से किसी गठबंधन का हिस्सा बनने को लेकर कुछ नहीं कहा था किन्तु बीते दिनों आरसीपी सिंह ने जन सुराज के कार्यलाय में पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। इसके साथ ही आरसीपी सिंह की 'आप सबकी आवाज' पार्टी का विलय भी पीके की जनसुराज के साथ हो गया।

गौरतलब है कि नई पार्टियों के साथ ही एक और दल चर्चा में है-राष्ट्रीय प्रगति पार्टी। राष्ट्रीय प्रगति पार्टी के अमरकांत साहू ने समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए और अपनी पार्टी का विलय कर दिया। अमरकांत साहू ने भामा शाह जयंती के मौके पर 29 अप्रैल को आरजेडी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लालटेन थाम लिया। अमरकांत साहू वैश्य समाज से आते हैं और उनको साथ लाकर आरजेडी की कोशिश वैश्य समाज के बीच अपनी जमीन बनाने की है। वही 'प्लूरल्स पार्टी' का नामकरण पिछले विधान सभा चुनाव के दौरान हुआ था। इस पार्टी के बारे में ज्यादा कुछ बताने को नहीं है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में यह अस्तित्व में आई थी। इस पार्टी की मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी भी बिहार में बदलाव की बात कहकर अपनी पार्टी लांच की थी। पुष्पम प्रिया चौधरी खुद दो जगहों से विधानसभा चुनाव लड़ी थीं, लेकिन दोनों जगहों से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पुष्पम प्रिया चौधरी अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतार सकती हैं। हालांकि उनकी रणनीति के बारे में अभी ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। वही इन तमाम पार्टियों के अलावा भी कुछ नए दल पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में नजर आएंगे। ऐसी पार्टियों की लिस्ट में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम भी शामिल हैं। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री हैं और दोनों की पार्टियां एनडीए में शामिल हैं। पशुपति पारस की पार्टी भी एनडीए में थी लेकिन बीते लोकसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने इस गठबंधन से एग्जिट करने का ऐलान कर दिया था। पशुपति पारस की पार्टी के लिए ये पहला चुनाव होगा। वहीं, चिराग और कुशवाहा की पार्टियां पिछले साल लोकसभा चुनाव अपने सिंबल पर लड़ चुकी हैं।

बहरहाल, बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन, दोनों ही गठबंधन घटक दलों के बीच की गांठें दुरुस्त करने में जुट गए हैं। एनडीए के घटक दलों के नेता जगह-जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, समन्वय बैठकें कर एकजुटता का संदेश दे चुके हैं। वहीं विपक्षी महागठबंधन भी तेजस्वी यादव की अगुवाई में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित कर चुका है। दोनों ही गठबंधन एकजुटता होकर

चिराग पासवान

पशुपति कुमार पारस

उपेन्द्र कुशवाहा

चुनाव मैदान में उतरने के दावे कर रहे हैं। ऐसे में बात उन छोटे दलों को लेकर भी हो रही है, जो गठबंधन की सियासत में अहम हो जाते है। बिहार में आज ऐसे ही छोटे, लेकिन अहम दलों में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का नाम आता है। बता दें कि चाचा पशुपति पारस की बगावत के बाद चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) नाम से अपनी पार्टी बनाई। चिराग की पार्टी सत्ताधारी एनडीए में शामिल है और वह खुद अपनी पार्टी के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री हैं। एलजेपी (आर) का बेस वोट दलित, पासवान वोटबैंक है। बिहार की जातिगत जनगणना के मुताबिक सूबे में 69 लाख 43 हजार पासवान हैं। यह सूबे की कुल जनसंख्या के अनुपात में देखें तो करीब 5.31 फीसदी है। यह आंकड़े अकेले जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में भले ही नहीं नजर आ रहे हों, किसी के साथ आ जाएं तो उसकी जीत के चांस जरूर बढ़ा सकते हैं। ऐसा पिछले चुनाव में देखने को भी मिला था, जब चिराग ने एनडीए से अलग राह ले ली थी और नीतीश की अगुवाई वाली जेडीयू की सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। जेडीयू सीटों के लिहाज से तीसरे नंबर पर खिसक गई तो उसके लिए नीतीश कुमार ने चिराग की पार्टी के सिर ही ठीकरा फोड़ा था। वही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी है। पशुपति पारस ने रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। पशुपति ने पार्टी के नाम और निशान पर दावेदारी कर केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन दे दिया था। पशुपति केंद्र में मंत्री भी रहे। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी का नाम-निशान फ्रीज कर दिया था। पशुपति ने आरएलजेपी नाम से अपनी पार्टी बनाई। इसका दावा भी पासवान वोटबैंक पर ही है। चिराग की पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हो गई थी। इसके बाद से ही पशुपति गठबंधन में हाशिए पर चले गए। आरएलजेपी को पिछले साल लोकसभा चुनाव में एनडीए ने एक भी सीट नहीं दी थी। पशुपति खुद अपनी सीट अपने लिए भी नहीं ले सके थे। अब वह एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पशुपति पारस की पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने के कयास हैं। पशुपति की पार्टी को

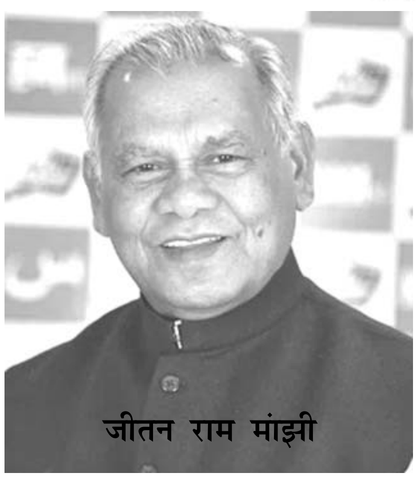
जीतन राम मांझी

साथ लाकर आरजेडी की रणनीति दलित मतदाताओं को संदेश देने की हो सकती है। दूसरी तरफ केंदीय मंत्री जीतनराम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (लोकतांत्रिक) एनडीए का घटक है। बिहार में एनडीए की अगुवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) कर रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी मुसहर जाति से आते हैं, जो महादलित कैटेगरी में शामिल है। मांझी की पार्टी जिस महादलित वोटबैंक पर दावा करती है, उसकी आबादी सूबे में करीब 14 फीसदी है। महादलित वर्ग में भी जीतनराम मांझी की अपनी जाति मुसहर की आबादी 3.09 फीसदी है। जीतनराम मांझी खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वहीं उनके बेटे संतोष सुमन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार में मंत्री हैं। अहम दलों में एक नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का भी आता है। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा (आरएलएम) भी सत्ताधारी एनडीए में शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा, कोइरी जाति से आते हैं। कोइरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लव-कुश (कुर्मी-कुशवाहा) समीकरण की एक अहम धुरी है। कोइरी समाज की आबादी बिहार में 4.21 फीसदी है। शून्य विधायकों वाली पार्टी आरएलएम की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में हार के बाद राज्यसभा से संसद में लाकर एनडीए ने केंद्र सरकार में

मुकेश सहनी

मंत्री बनाया। दूसरी तरफ मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) पिछले बिहार चुनाव में एनडीए के साथ थी। वीआईपी के उम्मीदवारों को चार सीटों पर जीत भी मिली थी, लेकिन बाद में यह सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। मुकेश सहनी इस बार विपक्षी महागठबंधन में हैं और सरकार बनने की स्थिति में डिप्टी सीएम के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो बिहार में सहनी यानी मल्लाह बिरादरी की आबादी 2.61 फीसदी है। वीआईपी निषाद वोटों पर दावेदारी जताती है। मल्लाह के साथ ही समाज की अन्य उपजातियों को भी जोड़ लें तो जातिगत सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक निषाद जाति की कुल आबादी 9.65 फीसदी पहुंचती है। एक-एक उपजाति के हिसाब से देखें तो अमात की जनसंख्या 0.21, केवट की 0.71, केवर्त की 0.20, कोल की 0.01, गोड़ी छाबी की 0.26, गोंड, 0.40, गंगई (गणेश) की 0.11 फीसदी है. गंगोता की 0.49, घटवार की 0.09, चायं की 0.07, तियर की 0.18, तुरहा की 0.35, घिमर की 0.0007, नोनिया की 1.91, बिंद की 0.98, बेलदार की 0.36, मझवार की 0.002 फीसदी आबादी है. निषाद समाज की उपजातियों में मोरियारी जाति की आबादी कुल आबादी का 0.019 और वनपर की आबादी 0.015 फीसदी है। इन छोटे दलों का वोट बैंक देखें तो दो से छह फीसदी के बीच है। देखने में यह आंकड़ों के कैनवास पर बहुत छोटा नजर आता है। यह वोटबैंक अकेले जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में भले ही न हो किन्तु किसी दल के साथ जुड़ जाए तो उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ाने की स्थिति में जरूर है। करीबी मुकाबले वाली सीटों पर इन छोटे-छोटे वोटबैंक वाली पार्टियां जीत-हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

सर्वविदित है कि बिहार में चुनाव हैं और चुनावी साल में भविष्य की चर्चा जोर पकड़ रही है। भविष्य बिहार की सत्ता का, राजनीतिक दलों का, नेताओं का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। सीएम नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और सर्वे रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री पद के लिए लोकप्रियता में आई कमी ने जनता दल (यूनाइटेड) अध्यक्ष के भविष्य को लेकर चर्चा को और हवा दे दी है। विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता नीतीश कुमार को थका बताकर युवा नेतृत्व को जरूरी बता रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों चुनावी चर्चा तो है ही, इसके समानांतर एक चर्चा और चल रही है- नीतीश कुमार की विरासत के दावेदार की। बिहार की सियासत दशकों तक लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शिष्यों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और जेडीयू की अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार तो पिछले तीन दशक से अधिक समय से बिहार का पावर सेंटर ही बने हुए हैं। सूबे की सियासत में अब नए-नए चेहरों की भी चर्चा हो रही है। बिहार में ऐसे ही पांच चेहरे ऐसे हैं, जो खुद को नीतीश की जगह सीएम की कुर्सी का दावेदार मानते हैं या दावेदार माने जा रहे हैं। इनमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदारों में प्रमुख चेहरा हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन के चुनाव अभियान की कमान संभाली थी और तब आरजेडी सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हाल ही में आई सी वोटर की सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी यादव 35.5 फीसदी लोगों की पसंद के साथ मुख्यमंत्री के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पर उभरे हैं। दूसरा नाम सम्राट चौधरी का आता है। सम्राट चौधरी बिहार सरकार के डिप्टी सीएम हैं। सी वोटर के सर्वे में 13 फीसदी लोगों ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बताया है। 56 साल के सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार के गठन के समय बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। सम्राट चौधरी की इमेज नीतीश कुमार के विरोधी की रही है। पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में भी विजय पताका फहराने की बात कही थी, तब सम्राट भी मंच पर मौजूद थे। सम्राट को आरजेडी ने 1999 में राबड़ी देवी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री बनाया था, तब वह दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हालांकि, उम्र कम पाए

नायाब सिंह सैनी

तेजस्वी यादव

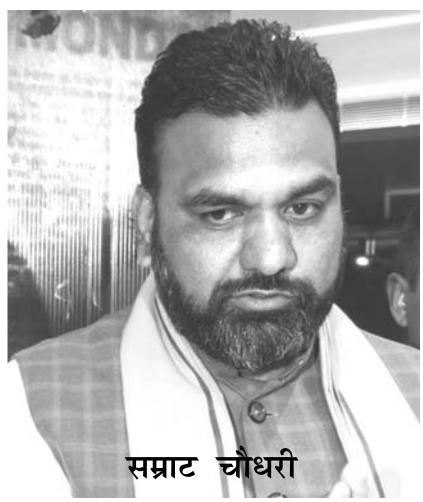

सम्राट चौधरी

चिराग पासवान

प्रशांत किशोर

पुष्पम प्रिया चौधरी

जाने पर राज्यपाल ने सम्राट को मंत्री पद से हटा दिया था। बिहार बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, जो नीतीश कुमार के लव-कुश (कुर्मी-कुशवाहा) समीकरण का भी अहम अंग है। सम्राट के पिता शकुनी चौधरी आरजेडी के मजबूत नेताओं में गिने जाते थे। शकुनी चौधरी कई बार सांसद और विधायक रहे। सम्राट चौधरी की माता पार्वती देवी भी मुंगेर के तारापुर से विधायक रही हैं। सम्राट चौधरी 2014 में जीतनराम मांझी की अगुवाई वाली सरकार का समर्थन करने वाले आरजेडी विधायकों में भी शामिल थे। वह 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए थे और 2018 में उन्हें पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया था। सम्राट 2023 में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने और 2024 तक इस पद पर रहे।

दिगर बात है कि चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर जन सुराज के सूत्रधार हैं। नई नवेली पार्टी जन सुराज के साथ बिहार के चुनावी रण में उतरने को तैयार पीके मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे हैं। सी वोटर के सर्वे में 17 फीसदी लोगों ने पीके को सीएम के लिए अपनी पसंद बताया है। पीके परिवारवाद, पलायन, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे मुखरता से उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी वादा कर रखा है कि जन सुराज की सरकार बनी तो एक घंटे के भीतर शराबबंदी समाप्त कर देंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी ने हाल ही में विधानसभा सीटों के उपचुनाव में करीब 10 फीसदी वोट शेयर के साथ दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। वही मुख्यमंत्री के दावेदारी पद की बात की जाये तो लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनकी सियासत का सेंटर प्वाइंट तो बिहार ही है। चिराग लंबे समय से 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' अभियान चला रहे हैं। 2020 के चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतार दिए थे। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, तो सीएम नीतीश ने इसके लिए चिराग की पार्टी को ही जिम्मेदार बताया था। युवा बिहार की यूथ पॉलिटिक्स का युवा चेहरा चिराग पासवान को सी वोटर के सर्वे में छः फीसदी लोगों ने सीएम पद के लिए पसंदीदा चेहरा बताया है। सनद् रहे कि बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव (2020) से पहले पुष्पम प्रिया चौधरी ने अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देकर खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। पुष्पम प्रिया की अगुवाई वाली प्लूरल्स पार्टी नाम से अपना दल बनाया और खुद दो सीटों से किस्मत आजमाई, लेकिन दोनों ही सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पुष्पम प्रिया के पिता विनोद कुमार चौधरी जेडीयू से एमएलसी भी रहे हैं।

बहरहाल, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सियासत में आने को लेकर अटकलों का दौर अभी तक जारी है। जेडीयू नेताओं का एक बड़ा तबका चाहता है कि निशांत कुमार राजनीति में आएं और पार्टी की बागडोर संभाले। हालांकि इस पर सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि, 14 मई को मुख्यमंत्री के सामने उनके ही गृह जिले नालंदा में कुछ ऐसा हो गया कि उन्हें इस विषय पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। दरअसल, सीएम नीतीश कुमार अपनी दिवंगत पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए नालंदा पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे निशांत कुमार भी थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने ही जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार के समर्थन में नारेबाजी की। जेडीयू कार्यकर्ताओं की ओर से 'बिहार का नेता कैसा

हो निशांत कुमार जैसा हो' और 'बिहार का भविष्य कैसा हो निशांत कुमार जैसा हो' के नारेबाजी के बीच नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों लोग काफी सहज नजर आ रहे थे। यह पहला मौका है जब निशांत कुमार राजनीतिक तौर पर एक्टिव नजर आए हैं। इस दौरान जब पत्रकारों ने निशांत कुमार से पूछा कि आप विशेष तौर पर नालंदा आए हैं क्या कहिएगा? इस पर उन्होंने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया कि हमारे पप्पू जी हैं, इन्होंने कहा था कि महिला क्रिकेट टूर्नामेंट है इसका शुभारंभ करना है उसी के लिए हम आए हैं। इसके साथ ही मेरी माता जी की पुण्यतिथि थी तो हमने उनकी समाधि पर माल्यार्पण किया है। इस घटना से ऐसा लग रहा है कि शायद निशांत कुमार राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं और जल्द ही इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा भी कर दी जाएगी। पिछले कुछ समय से लगातार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। निशांत लगातार अपने बयानों से मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। आए दिन वो किसी न किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं। जिस वजह से उनका चुनावी राजनीति में शामिल होने की संभावना

जताई जा रही है। जहाँ अब तक निशांत कुमार राजनीति से दूर और बेहद निजी जीवन जीते रहे, वहीं यह वीडियो उनके बदलते रुख का संकेत माना जा रहा है। जेडीयू के युवा कार्यकर्ताओं में उन्हें लेकर उत्साह साफ नजर आता है। सवाल उठ रहा है कि, क्या निशांत कुमार बनेंगे बिहार की सियासत का अगला चेहरा? क्या पिता नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत अब बेटे के हाथों में जाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सियासी मैदान में हलचल शुरू हो चुकी है।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार बैठकों का दौर जारी है। हालिया बैठक में तय किया गया कि एनडीए विकास के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए चुनाव लड़ेगा। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी तैयार की गई है जिसमें 2005 से पहले की स्थिति और वर्तमान की तस्वीर को दिखाया गया है। एनडीए का फोकस यह दिखाने पर है कि राज्य ने बीते दो दशकों में कितनी तरक्की की है। एनडीए द्वारा तैयार की जा रही डॉक्यूमेंट्री

निशांत कुमार

नीरज कुमार

ऋतुराज सिन्हा

मृत्युंजय तिवारी

में विशेष रूप से यह दिखाया जाएगा कि 2005 से पहले यानी आरजेडी शासनकाल में बिहार की क्या स्थिति थी और अब क्या है? जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा का कहना है कि यह फिल्म लोगों को सच्चाई दिखाएगी और एनडीए के विकास कार्यों को उजागर करेगी। इसके जरिए वे जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन ने एनडीए के इस अभियान को "रिलीज से पहले ही फ्लॉप" करार दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि जनता बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। एनडीए के पास बताने के लिए कुछ नया नहीं है, इसलिए वो पुराने मुद्दों को बार-बार उछाल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी आरोप लगाया कि एनडीए जनता को "घिसी-पिटी कहानियों" से भरमाना चाहती है। महागठबंधन ने स्पष्ट किया है कि वह भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजगार और किसानों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगा। उनका कहना है कि एनडीए सरकार के कई पदाधिकारी और नीति निर्माता खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महागठबंधन इस बार जन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरकर सरकार को घेरने की

राजेश राठौर

रणनीति बना रहा है। एक ओर जहां एनडीए बिहार के विकास को केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार करेगा, वहीं विपक्ष सरकार की विफलताओं को उजागर करेगा। यानी चुनाव प्रचार में इस बार 'विकास बनाम विफलता' की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके रिपोर्ट कार्ड को पास करती है। वही बता दें कि पिछले कुछ चुनावों से लाडली बहना पॉलिटिक्स राजनीतिक दलों के लिए चुनावी जीत की गारंटी बन गया है। मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र या फिर झारखंड, इन राज्यों में महिलाओं को दिया गया डायरेक्ट कैश बेनिफिट सत्ताधारी दलों के लिए सरकार बनाने का वरदान साबित हुआ। वहीं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली के चुनाव में कैश बेनिफिट का वादा जीत की कुंजी बन गया। अब हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। बिहार चुनाव के दिन जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, लाडली बहन पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का अघोषित चेहरा माने जा रहे तेजस्वी यादव सत्ता में आने पर माई-बहिन मान योजना लाकर महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये भेजने का वादा कर चुके हैं। तेजस्वी के इस दांव को काउंटर करने के लिए 'लाड़ला मुख्यमंत्री' नीतीश कुमार की सरकार के भी जुलाई तक ऐसी कोई योजना लागू करने की चर्चा है। हालांकि, सरकार या सत्ताधारी गठबंधन में शामिल किसी दल की ओर से इसे लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। सवाल उठ रहा है कि बिहार चुनाव से पहले सूबे में लाडली बहन पॉलिटिक्स की चर्चा क्यों हो रही है? तो

बता दें कि बिहार में लाडली पॉलिटिक्स की चर्चा के पीछे महिला मतदाताओं की तादाद और वोटिंग पैटर्न भी वजह है। 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की तादाद बढ़कर 7 करोड़ 80 लाख पहुंच गई है। महिला मतदाताओं की संख्या भी 3 करोड़ 72 लाख के करीब है। पिछले कुछ चुनावों का वोटिंग पैटर्न देखें तो महिला मतदाता वोट डालने के लिए पुरुषों के मुकाबले अधिक संख्या में घर से निकली हैं। महिलाओं वोटर्स का टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले अधिक रहा है। साल 2010 के बिहार चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में वोट डालने के मामले में महिलाएं आगे रही थीं। तब पुरुषों का टर्नआउट 53 और महिलाओं का 54.5 फीसदी रहा था। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 115 सीटें मिली थीं। 2015 में 51.1 फीसदी पुरुषों के मुकाबले 60.4 फीसदी महिलाओं ने मतदान किया था। 2020 के बिहार चुनाव में जहां 54.6 फीसदी पुरुषों ने वोट किए थे। इस चुनाव में भी 59.7 फीसदी महिलाओं ने वोट किया था, जो पुरुषों के मुकाबले 5 फीसदी अधिक है। वही महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का साइलेंट वोटर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के

तमाम बड़े नेता अलग-अलग राज्यों के चुनाव में मिली जीत के लिए महिला मतदाताओं को श्रेय दे चुके हैं, लेकिन बिहार में तस्वीर थोड़ी अलग है। बिहार में महिला वोटबैंक को नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू का कोर वोटर माना जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी लगातार 16 फीसदी के आसपास वोट शेयर बरकरार रखने में सफल रही है, तो उसके पीछे भी इसी महिला वोटबैंक की भूमिका मानी जाती है। बताते चले कि माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने के आरजेडी के वादे और लाडली पॉलिटिक्स को लेकर कहा जा रहा है कि कैश बेनिफिट का दांव चुनावी राजनीति का सफल फॉर्मूला बनकर सामने आया है, लेकिन बिहार में देखना होगा कि यह कितना सफल हो पाता है। शराबबंदी जैसे कदमों से महिलाओं के बीच अपनी सियासी जमीन बनाने वाले नीतीश कुमार ने साइकिल योजना से लेकर आजीविका तक, महिला केंद्रित कई योजनाएं चलाईं। नीतीश अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से महिलाओं तक बेनिफिट पहुंचाते आए हैं। ऐसे में बिहार चुनाव इस दांव का भी टेस्ट होगा।

सर्वविदित हो कि महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह हो या जेपी की संपूर्ण क्रांति, देश की सियासत को दिशा दिखाते आए बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी तैयारियों में जुटी सियासी पार्टियां अपना-अपना 'वोट गणित' सेट करने में जुट गई हैं। अगले पांच साल तक बिहार की सत्ता पर किसका राज होगा? यह तय करने के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान अभी होना है लेकिन तैयारियों के मोर्चे पर डुगडुगी बज चुकी है। हर दल का फोकस युवा आबादी पर है। बिहार की कुल आबादी में 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की हिस्सेदारी आधे से अधिक है। 2023 के जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 है। इसमें से करीब 58 फीसदी आबादी 25 साल से कम उम्र के युवाओं की है। युवा आबादी के लिहाज से देखें तो देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले राज्य में चुनाव से पहले हर दल संख्याबल के लिहाज से इस बड़े वर्ग को साधने, अपने पाले में लाने की

कवायद में जुटा दिख रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले युवा बिहार की सियासत का सेंटर प्वाइंट बन गए हैं। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) हो या विपक्षी महागठबंधन या फिर बिहार में चुनावी डेब्यू करने को तैयार जन सुराज, हिंद सेना और इंडियन इंकलाब पार्टी जैसे दल; सभी का फोकस युवाओं पर है। लोकतंत्र में संख्याबल का ही महत्व है। संख्याबल के लिहाज से देखें तो युवा वर्ग जातीय गणित में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) आबादी हटा दें तो बाकी वर्गों की कुल आबादी से भी अधिक है। नैरेटिव की जंग भी एक बड़ी वजह है। एक वजह यह भी हो सकती है कि राजनीतिक दलों की कोशिश जातीय राजनीति मकड़जाल में उलझी बिहार की सियासत में इस भावना से परे अलग-अलग जाति, वर्ग के लोगों को एक बैनर तले लाया जाए। युवाओं को लेकर हिंदी पट्टी का एक बहुत चर्चित नारा रहा है-'जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है'। साल 2014 के आम चुनाव और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विजय रथ के पीछे भी युवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को श्रेय दिया जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) 75 विधानसभा सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा और उसकी अगुवाई वाला महागठबंधन 110 सीटें जीतने में सफल रहा, तो इसके पीछे 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे का बड़ा रोल माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव

में 40 में से महज एक सीट ही जीत सके महागठबंधन को 2024 में नौ सीटें जीतने में सफल रहा तो इसके पीछे भी युवाओं के बीच तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को ही वजह बताया गया। बिहार की युवा आबादी

की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा और रोजगार है। सामाजिक समस्या की शक्ल ले चुका पलायन भी अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। पलायन करने वाली आबादी में बड़ी भागीदारी अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार की चाह रखने वाले युवाओं की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (केंद्रीय) के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के करीब तीन करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। हर साल करीब 50 लाख लोग शिक्षा और रोजगार के लिए बिहार से पलायन करते हैं। सनद् रहे कि युवा मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी पार्टियों की भी अपनी-अपनी रणनीति है। एनडीए के सबसे बड़े घटक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की रणनीति ही युवाओं पर केंद्रित रहती है। पीएम मोदी ऐसे युवाओं को राजनीति में लाने के मिशन का ऐलान भी कर चुके हैं, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। सम्राट चौधरी जैसे फेस को आगे करना भी बीजेपी की यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स से जोड़कर ही देखा जाता है। बिहार में एनडीए सरकार की अगुवाई कर रही जनता दल (यूनाइटेड) नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते रोजगार की दिशा में किए काम जनता के बीच लेकर जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2020 में सात निश्चय-दो लागू होने के बाद 9 लाख 38 हजार से अधिक लोगों को सरकार नौकरियां दिए जाने, विधानसभा चुनाव तक सरकारी नौकरी पाने वालों की संख्या 12 लाख के पार पहुंचने के दावे कर रहे हैं। नीतीश कुमार सरकारी नौकरियों समेत 50 लाख लोगों को रोजगार बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। चिराग पासवान भी युवाओं को एनडीए के पक्ष में एकजुट करने की कवायद में जुटे हैं। तेजस्वी यादव और आरजेडी नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के समय सरकारी नौकरियों को अपनी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। वहीं, कांग्रेस ने भी कन्हैया कुमार के रूप में अपना युवा चेहरा आगे कर दिया है। युवाओं के बीच महागठबंधन की जमीन मजबूत करने को कोशिश में कन्हैया कुमार ने 'पलायन रोको, रोजगार दो' पदयात्रा निकाली थी। चुनाव रणनीतिकार से

राजनेता बने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) पलायन के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। पीके यह वादा कर रहे हैं कि 10 हजार तक के रोजगार के लिए युवाओं को बिहार से बाहर नहीं जाना होगा। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी शिवदीप लांडे की हिंद सेना और पान समाज के आईपी गुप्ता की इंडियन इंकलाब पार्टी का टार्गेट भी वोटर युवा ही है। सभी दल पलायन रोकने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन रोकेंगे कैसे? इसे लेकर कोई फूलप्रूफ प्लान किसी के पास नहीं है।

बहरहाल, बिहार में राजनीतिक परिदृश्य गर्म हो रहा है, दोनों प्रमुख गठबंधनों की ओर से सक्रियता बढ़ रही है। एनडीए अपनी संभावनाओं को लेकर आशावादी है, ऑपरेशन सिंदूर और मोदी और नीतीश के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार से उत्साहित है। इस बीच, राहुल गांधी के लगातार दौरे राज्य में प्रभाव डालने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर बिहार की राजनीतिक बहस का केंद्र बिंदु बन गया है। इस मुद्दे पर जहां ज्यादातर विपक्षी दल सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के कामों पर

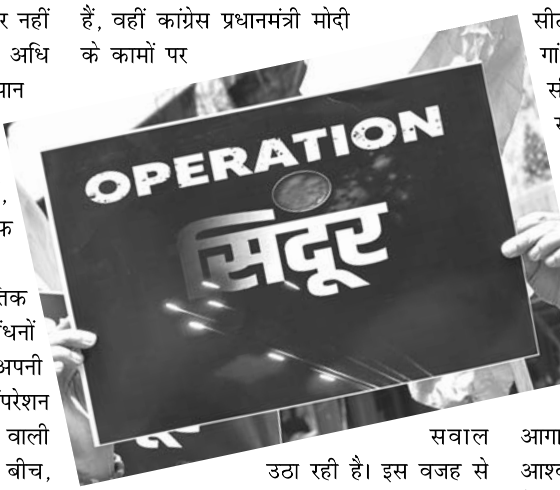

सवाल उठा रही है। इस वजह से इस मामले पर आगे चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग उठ रही है। कांग्रेस का लक्ष्य पिछले चुनावों की तरह बिहार में करीब 70 सीटों पर चुनाव लड़ना है। हालांकि, सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी के साथ तनाव पैदा हो गया है, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस को 50-60 सीटों तक सीमित रखना चाहती है। राहुल गांधी का मुखर रुख आरजेडी पर अधिक सीटें देने के लिए दबाव बनाने का प्रयास हो सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद, राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस की मौजूदगी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पार्टी के कुछ सदस्यों का मानना है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस को समय के साथ राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिल सकती है। वही बिहार में जाति आधारित राजनीति पर अपनी पकड़ के कारण एनडीए आगामी चुनावों में अपनी संभावनाओं को लेकर आश्वस्त है। मोदी-नीतीश की जोड़ी को उम्मीद है कि उनके शासन का रिकॉर्ड मतदाताओं को पसंद आएगा और उनके गठबंधन को जीत मिलेगी। हालांकि, कांग्रेस के लिए आरजेडी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों से पार पाना आसान नहीं होगा। आरजेडी का दलित मतदाताओं के बीच मजबूत आधार है और उसके पास मजबूत एमवाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण है, जो राहुल गांधी के प्रयासों के लिए चुनौती बन सकता है। दोनों गठबंधन चुनावी जंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह अनिश्चित है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरे भारत में मतदाताओं की भावनाओं को कैसे प्रभावित करेगा। इस चुनाव के नतीजे ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रीय मूड के बारे में जानकारी दे सकते हैं। दूसरी तरफ बिहार में राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस रहे हैं, अखिल भारतीय गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) जैसे प्रमुख गठबंधन अपनी सीटों की संख्या को अधिकतम करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। इस तैयारी के बीच, इन गठबंधनों के भीतर छोटे दलों के बीच सीटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हासिल करने के

लिए स्पष्ट रूप से होड़ मची हुई है, जो अपने बड़े सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपना रहे हैं। एनडीए के खेमे में, इसके घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। बिहार के सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि भाजपा और जनता दल (युनाइटेड) प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा गठबंधन के अन्य घटक दलों के लिए सिर्फ 43 सीटें छोड़ी जाएंगी। वहीं एनडीए के कई दलों की ओर से ज्यादा सीटों की मांग को लेकर पारा चढ़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 20-30 सीटें मांग रही है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 40-50 सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक 10-15 सीटों की मांग कर रहे हैं। यह एनडीए के भीतर मतभेद की वजह बन सकती है। बिहार में बन रहे सियासी समीकरण और मांगों पर भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी संजय मयूख ने कहा कि बिहार में गठबंधन एकजुट और मजबूत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है और सीटों के बंटवारे के बारे में उचित समय पर जानकारी दी जाएगी। एनडीए में सीटों को लेकर कोई भ्रम नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर भी एनडीए के तरह ही सीट बंटवारे को लेकर खिचड़ी पक रही है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के साथ-साथ सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआई (एमएल) और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) से मिलकर बना यह गठबंधन अपने सदस्यों के बीच ज्यादा सीटों की मांग को लेकर भी विचार कर रहा है। 2020 के विधानसभा चुनावों में 19 में से 12 सीटें हासिल करने के बाद सीपीआई (एमएल) आगामी चुनावों में कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य बना रही है। इसी तरह, सीपीआई और सीपीआई (एम) दोनों 30-40 सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा जताया है। इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर चल रहे मतभेदों बावजूद, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर आशावादी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है, समय के साथ अपने आप मसले हल हो जाएंगे। महागठबंधन के दल अपनी वैचारिक लड़ाई में एकजुट है और समय आने पर सीट बंटवारे का गणित भी आसानी से हल हो जाएगा। बिहार में राजनीतिक परिदृश्य इन घटनाक्रमों के साथ गर्म हो रहा है, दोनों प्रमुख गठबंधन सीट आवंटन की आंतरिक चुनौतियों के बीच एकता और सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों में यह पता चलने की संभावना है कि ये बातचीत किस तरह आगे बढ़ती है, जिससे विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी टक्कर का माहौल तैयार हो जाएगा।

गौरतलब है कि '25 से 30, फिर से नीतीश', ये स्लोगन पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्ट पर लिखा है। जब भी बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान आता है जिसकी वजह से नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री बन पाना शक के दायरे में आ जाये, जेडीयू की तरफ से ऐसा कदम जरूर उठाया जाता है। कभी जेडीयू प्रवक्ता मीडिया के सामने आकर दावे करते हैं, तो कभी ऐसे पोस्टर लगा दिये जाते हैं। कभी-कभी सोशल मीडिया पर भी ऐसे पोस्टर शेयर करके कैंपेन चलाया जाता है। जेडीयू में ताजा बवाल मचा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान से। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान नायब सैनी ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम लिया और बीजेपी की चुनावी फतह की बात कर दी, और नीतीश कुमार कैंप में नये सिरे से हड़कंप मच गया। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी मोर्चे पर आ डटे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हवाला देते हुए मीडिया के सामने दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और

नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। निशांत कुमार पहले भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाने का दावा कर चुके हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में मुश्किल से छः महीने बचे हैं और नीतीश कुमार की कुर्सी पर मंडराते संकट के बादल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आखिर ऐसी चीजों को हवा क्यों दे रही है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बस इतना ही कहा था कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार चुनाव में बीजेपी विजय पताका फहराएगी और ये सुनते ही जेडीयू नेता एक्टिव हो गये। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में नायब सैनी ने कहा था कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है, ये विजय का पताका रुकना नहीं चाहिये। ये विजय का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। जब जेडीयू नेताओं की तरफ से आपत्ति जताई गई तो सम्राट चौधरी सहित बिहार बीजेपी के नेताओं ने सफाई दी कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा हैं और आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मीडिया के सामने आये हैं और कह रहे हैं, अमित अंकल (केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह) भी कह चुके हैं कि पिताजी (मुख्यमंत्री नीतीश कुमार) के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। निशांत कुमार का ये भी दावा है कि नीतीश कुमार सौ फीसदी फिट हैं, लेकिन ये दावा हकीकत से मेल नहीं खाता। नीतीश कुमार के कुछ सार्वजनिक ऐक्ट पर सवाल उठने लगे हैं। उनके राजनीतिक विरोधी तो उनकी सेहत को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग तक कर डाले हैं। बिहार बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल का भी कहना है कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, लेकिन अंतिम मुहर संसदीय बोर्ड ही लगाएगा। मतलब, तब तक मानकर चलना चाहिये कि कुछ भी हो सकता है। अमित शाह ने भी तो ऐसा ही कहा था, लेकिन जब जेडीयू की तरफ से शोर मचाया जाने लगा तो बिहार बीजेपी के नेताओं ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान भी नीतीश कुमार कैंप की टेंशन बढ़ाने वाला रहा। अश्विनी चौबे ने सुझाव दे डाला कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाना चाहिये। मतलब, तो यही हुआ कि नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिये। डिप्टी पीएम बनाया जाना तो पक्का नहीं है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर शक जरूर पैदा हो सकता है। कुछ दिनों पहले गिरिराज सिंह ने तो नीतीश कुमार को भारत रत्न दिये जाने की मांग कर डाली थी। गिरिराज सिंह लंबे अर्से से नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी रहे हैं और उनकी तरफ से भारत रत्न दिये जाने की मांग तो कटाक्ष ही लगता है। गिरिराज सिंह के बयान को भी जेडीयू नेताओं ने ऐसे ही समझा कि बताया जा रहा हो कि नीतीश

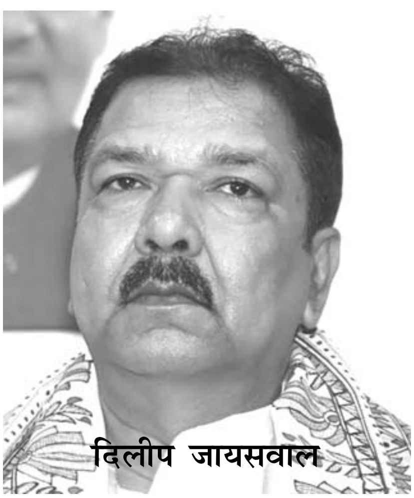
दिलीप जायसवाल

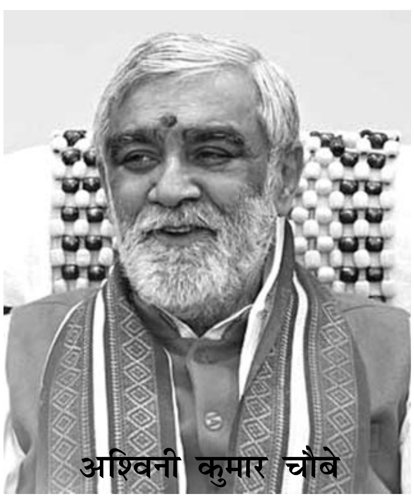
अश्विनी कुमार चौबे

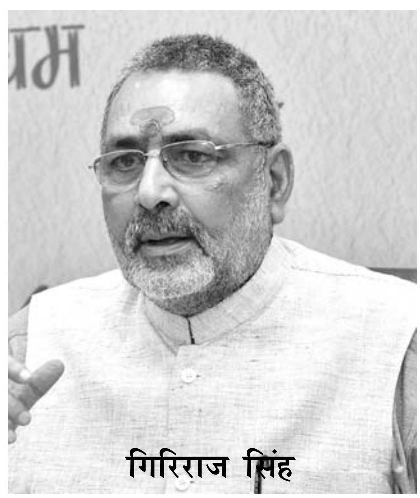
गिरिराज सिंह

कुमार का कद इतना ऊंचा है कि उनको अब मुख्यमंत्री बना कर नहीं रखा जा सकता। अब सवाल है कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा क्यों लग रहा है? क्योंकि, बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, लेकिन अभी तक उसे नीतीश कुमार के कद का कोई नेता नहीं मिल पाया है। सम्राट चौधरी को भी इसी मकसद से सामने लाया गया है, क्योंकि वो भी नीतीश कुमार के लव-कुश समीकरण में फिट बैठते हैं, लेकिन अब तक वो ऐसा कुछ नहीं दिखा पाये हैं जिससे बीजेपी नेतृत्व उन पर भरोसा करके दांव लगा सके। वही नीतीश कुमार के पास पाला बदलने का भी स्कोप करीब-करीब खत्म हो चुका है। वक्फ बिल पर संसद में बीजेपी का सपोर्ट करके नीतीश कुमार अपने मुस्लिम वोटर को भी नाराज कर चुके हैं तभी तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मुर्शिदाबाद हिंसा पर बात करते हुए उनका नाम भी घसीट ले रही हैं। साथ ही लालू यादव भी बेटे तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और कांग्रेस नेतृत्व भी नीतीश कुमार से खफा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बिहार में एंट्री की पूर्व संध्या पर ही नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम लिया था और सबसे अहम कि नीतीश कुमार की सेहत भी साथ नहीं दे रही है। अब तो वो पहले की तरह राजनीति भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे किसी तरह 'खेला' कर दिये जाने की कोई संभावना बनती हो।

हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा काम शराबबंदी का किया। यह कोई नीतीश कुमार का ऑरिजिनल चिंतन नहीं था। बल्कि यह दृष्टि उन स्त्रियों ने दी जो पियक्कड़ पतियों या पिताओं से बुरी तरह प्रताड़ित थीं। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया कर आधी आबादी का विश्वास और ज्यादा हासिल कर लिया।

सत्ता की राजनीति की बागडोर थामने के बाद स्थिरता की तलाश का पहला कदम नीतीश कुमार ने 2005 में ही रख दिया था। लेकिन थोड़े से अंतराल के बाद नीतीश कुमार वर्ग की राजनीत का दांव खेल जाते और अपनी यूएसपी के साथ साथ फॉलोवर भी बढ़ाते रहे। ज्ञात हो कि साल 2006 था जब नीतीश कुमार ने आधी आबादी को टारगेट करते 2006 के बाद महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय के चुनाव में 50 प्रतिशत की भागीदारी दी। इससे बड़े पैमाने पर महिलाएं घरों से निकल कर समाज में आत्मनिर्भर हुई हैं। इन सब वजहों से महिलाओं का सम्मान समाज और परिवार में काफी बढ़ा भी। वही शिक्षा के प्रति छात्राओं को प्रोत्साहित करने के मकसद से राज्य में बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की शुरुआत 2011 में नीतीश कुमार ने की। इसका भी असर स्कूलों के नामांकन पर दिखा। जहां छात्राओं का एडमिशन 33 फीसदी रहा करता था, वो इन योजनाओं को लागू करने के बाद 97 फीसदी तक जा पहुंचा। नौवीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए इस योजना की शुरुआत सत्र 2011-12 में की गयी थी। शुरुआत में नौवीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को हजार रुपये प्रतिवर्ष की राशि दी जाती थी। 2018-19 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया। इसके साथ ही साल 2016 में नीतीश कुमार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में संख्या बढ़ाने के लिए आरक्षण देने का फैसला किया। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में मिली सहमति के बाद सरकार ने सभी नौकरियों के सभी पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण दे कर परिवर्तन की आंधी बहा दी। सरकार ने आरक्षित और गैर आरक्षित श्रेणी में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय कर ऐतिहासिक फैसला कर डाला।

बहरहाल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहला तो यह नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव दिखता है और दूसरा बड़ा कारण उनकी इस इच्छा का है जो अपने पुराने वैभव यानी साल 2010 में हासिल 115 सीट से ज्यादा पाने का है। इस बड़े सपने के लिए नीतीश कुमार ने फिर से आधी आबादी पर भरोसा कर महिला संवाद कार्यक्रम को शुरू किया। कोशिश यह है कि आधी आबादी ने 2010 की तरह साथ दे दिया तो 2025 में भी चुनावी लक्ष्य आराम से हासिल हो जाए। हालांकि तेजस्वी ने इसके पहले माई बहिन सम्मान योजना का ऐलान किया। लेकिन ये भी सच है कि इस मामले में आधी आबादी को नीतीश पर ज्यादा भरोसा दिखता है।

खैर, अब यह तो समय के गर्भ में है कि इस बार महिला वोट तेजस्वी अपने पक्ष में कर पाएंगे या फिर से उन्हें नीतीश के सामने मुंह की खानी पड़ेगी। ●

● **संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)**

हाल के वर्षो में भारतीय राजनीति में जिस तरह से सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हर मुद्दे पर तलवारें खींची नजर आती थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से दोनों धड़ों में एकजुटता देखने को मिल रही है, उससे देश की आम जनता काफी खुश है, वहीं पाकिस्तान में इसके उलट नजारा नजर आ रहा है। पड़ोसी मुल्क में विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोसने और उन्हें नाकाबिल नेता साबित करने में लगा है। मोदी और शरीफ की तुलना शेर और सियार के रूप में की जा रही है।

बहरहाल, भारत के लिये यह सुखद है कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार के हर कदम पर विपक्ष बिना किसी शर्त के पूरी मजबूती से खड़ा है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक अद्भुत परिवर्तन देखा गया है। विपक्षी दलों ने इस बार न केवल

सरकार का समर्थन किया बल्कि सेना के साहस और कार्रवाई की खुलकर सराहना की। इससे पहले उरी और पुलवामा हमलों के बाद जिस तरह से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे, और बीजेपी ने उन्हें राष्ट्र विरोधी खांचे में रखकर सियासी नुकसान पहुंचाया था, उस पृष्ठभूमि में यह बदलाव बेहद अहम है। यह न केवल राजनीति की परिपक्वता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत अब एक स्वर में बोल रहा है। गौरतलब हो, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले ने न केवल आम जनता की भावनाओं को आहत किया, बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर दी थी कि वे इस मुद्दे को किस रूप में लें। कांग्रेस और अन्य प्रमुख दलों ने बिना देर किए केंद्र सरकार को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने सुरक्षा और खुफिया तंत्र की संभावित चूक का मुद्दा उठाने के बावजूद, इसे राजनीति का विषय नहीं बनने दिया। यह देश की एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए विपक्ष का एक परिपक्व और जिम्मेदार रवैया था।

भारतीय सेना ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक और प्रभावशाली कार्रवाई की। सेना की इस जवाबी कार्रवाई को

विपक्ष की ओर से न केवल समर्थन मिला बल्कि सराहना भी हुई। कोई सवाल नहीं, कोई प्रमाण की मांग नहीं, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं बस एक सुर में सरकार और सेना के साथ खड़े रहने की भावना। 'भारत माता की जय' और 'जय हिंद' के नारों के साथ विपक्षी नेता भारतीय सेना के साथ नजर आए। यह एक ऐसी तस्वीर थी जो 2016 के उरी हमले या 2019 के पुलवामा हमले के बाद नजर नहीं आई थी। उरी हमले के बाद जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उस पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी के तौर पर पेश करके राजनीतिक लाभ उठाया था। ठीक ऐसा ही पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान हुआ था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सबूत मांगे थे, जिसके चलते पार्टी को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी ने भी सेना के शौर्य पर विश्वास जताने के साथ-साथ पीएम मोदी पर जवानों के बलिदान की राजनीति करने का आरोप लगाया था। इन बयानों से कांग्रेस को चुनावी मैदान में भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार कहानी बदली हुई है।

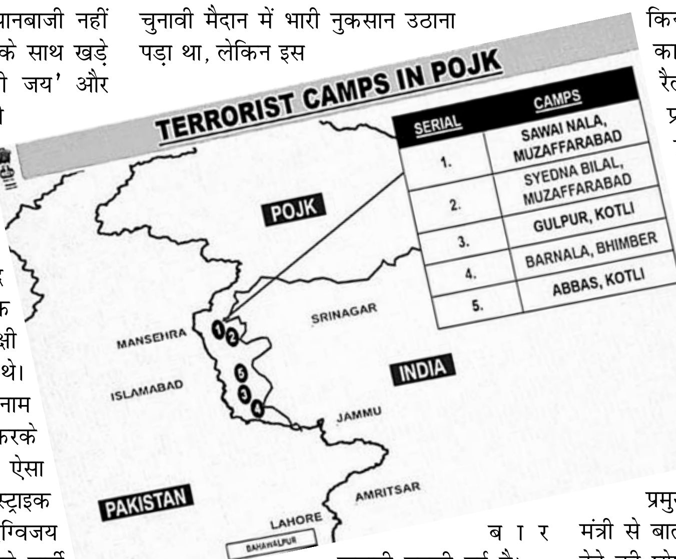

ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को रोक दिया, पार्टी की सर्वोच्च नीति-निर्धारण संस्था कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक बुलाई गई और राहुल गांधी ने स्वयं सेना को समर्थन देने का ऐलान किया। प्रियंका गांधी वाड्रा के सुझाव पर कांग्रेस ने अपनी 'संविधान बचाओ' रैली स्थगित कर दी, ताकि सेना के प्रति एकजुटता और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश स्पष्ट रूप से जाए। यहां तक कि कर्नाटक कांग्रेस ने भी अपनी उस सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया, जिसमें शांति को सबसे बड़ा हथियार बताया गया था जो शायद मौजूदा माहौल में सेना के ऑपरेशन के संदर्भ में गलत संदेश दे सकती थी। कांग्रेस के इस नए रुख के साथ ही अन्य विपक्षी दल भी उसी दिशा में नजर आए। एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बात करके अपनी पार्टी का पूरा समर्थन देने की घोषणा की। यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे ए के एंटनी, जो अक्सर मोदी सरकार के आलोचक रहे हैं, उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर को 'एक मजबूत शुरुआत' बताया और सेना की

निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहुल गांधी के शब्दों की आलोचना कर चुके थे, उन्होंने भी इस बार सेना के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरा देश एकजुट है।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर सराहना की और जवानों को सलाम किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो अक्सर मोदी सरकार के आलोचक रहते हैं, उन्होंने भी इस बार सरकार के सुर में सुर मिलाया और पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई की प्रशंसा की। यहां तक कि वामपंथी दलों ने, जो आमतौर पर सैन्य कार्रवाई पर संयम बरतने की बात करते हैं, उन्होंने भी पहलगाम हमले के बाद सरकार और सेना के साथ खड़े होने की बात कही। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने भी माना कि इस बार भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह पूरा घटनाक्रम भारतीय राजनीति के लिए एक नई दिशा का संकेत है। यह दर्शाता है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दे पर अब राजनीतिक दल न केवल एकजुट हैं, बल्कि अपने पुराने सियासी रवैये की भी समीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस का यह नया रुख जहां उसे राष्ट्रवादी विमर्श में खुद को फिट करने में मदद करेगा, वहीं अन्य विपक्षी दलों के लिए भी यह संदेश है कि जनता अब केवल आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि एकजुटता और जिम्मेदारी की राजनीति देखना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति न तो नरम है, न ही विभाजित। यह केवल केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि विपक्ष की परिपक्व भागीदारी का भी प्रतिबिंब है। अगर इस रुख को भविष्य में भी कायम रखा गया, तो यह न केवल देश की आंतरिक राजनीति को परिपक्व बनाएगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत की छवि को और सुदृढ़ करेगा।

बात पाकिस्तान की कि जाये तो वहां सेना, सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खींची हुई हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सैन्य और रणनीतिक स्थिति डगमगाई हुई है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सियासत भी बुरी तरह बिखर गई है। जब देश को एकजुट होकर संकट का सामना करना चाहिए, तब पाकिस्तानी नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच बढ़ती खींचतान ने पूरे मुल्क को असमंजस में डाल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने मौजूदा सरकार पर सेना के साथ मिलीभगत और गलत फैसलों का आरोप लगाया है, वहीं सरकार का कहना है कि इमरान खान जैसे नेता युद्ध के समय भी राष्ट्रविरोधी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। संसद में तीखी बहस के दौरान विपक्षी नेताओं ने सेना की विफलताओं पर सवाल खड़े किए, जिससे देश की अंतरराष्ट्रीय छवि और कमजोर हुई। इस बीच, पाकिस्तानी सेना और सरकार के बीच भी समन्वय की कमी साफ नजर आ रही है। मीडिया में लीक हो रही जानकारियों के मुताबिक, कई रक्षा फैसलों पर सेना और सरकार की राय अलग-अलग रही है, जिससे फ्रंट पर रणनीतिक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इससे देश के आम नागरिकों में असुरक्षा और निराशा का माहौल है। जानकार मानते हैं कि इस समय पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा भारत से नहीं, बल्कि अपनी बिखरी हुई राजनीतिक नेतृत्व और कमजोर रणनीतिक सोच से है। ●

सीजफायर : मोदी की राष्ट्रवाद से यू-टर्न तक की अधूरी कहानी

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

भारतीय राजनीति में ऐसे कई क्षण आते हैं जब कोई घटना देश की जनता और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच संबंधों को गहराई से प्रभावित करती है। पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में 26 हिन्दुओं की हत्या भी इसी की एक कड़ी थी, जिसका हिसाब चुकाने के लिये मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कड़ा कूटनीतिक और सैन्य प्रहार किया, जिसकी शुरूआत पाकिस्तान के साथ दशकों पुराने चले आ रहे सिंधु जल समझौते के निलंबन से हुई तो 'ऑपरेशन सिंदूर' के रूप में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस कर ही आतंकवादियों को कब्र में सुला दिया, आपरेशन सिंदूर एक ऐसी ही सैन्य कार्रवाई थी, जो जितनी तेजी से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आई, उतनी ही जल्द वह विवादों और अस्पष्टताओं के भंवर में फंसकर थम गई। यह ऑपरेशन अपने कथित उद्देश्यों के कारण जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही इसके अचानक ठहराव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए। जब पहलगाम में आतंकियों ने 26 हिन्दुओं को उनका धर्म पूछ कर मारा तो इसका बदला लेने के लिये पूरा देश और विपक्ष मोदी सरकार के साथ खड़ा हो गया। सबने एक सुर में कहा मोदी सरकार जो कार्रवाई करेगी, उसका हम समर्थन करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबको संतुष्ट करने में कोई गुरेज नहीं किया, लेकिन जब सीजफायर किया गया तो मोदी सरकार ने किसी से नहीं पूछा। उन विपक्षी नेताओं को भी भरोसे में नहीं लिया जो उनके साथ खड़े हुए थे, यह बात देशवासियों को पसंद नहीं आई। खासकर बीजेपी और मोदी समर्थक भी इस मुद्दे पर बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ नजर आये।

गौरतलब हो 'ऑपरेशन सिंदूर' की शुरुआत एक गुप्त अभियान के तौर पर हुई थी, जिसका उद्देश्य कथित रूप से कश्मीर घाटी में आतंक के नेटवर्क को समाप्त करना और पाकिस्तान समर्थित तत्वों को निष्क्रिय करना था। इस ऑपरेशन का नाम 'सिंदूर' रखने के पीछे भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतीक था। सिंदूर, जो भारत में सुहागिन स्त्रियों का प्रतीक है। माना जा रहा था कि इस ऑपरेशन के तहत सुरक्षाबलों को 'फ्री हैंड' दिया

गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के मार्गदर्शन में इसे अंजाम तक पहुंचाया जाना था। ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में कुछ महत्वपूर्ण गिरफ्तारियाँ और सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकी ठिकानों पर हमले हुए भी थे। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीते, यह ऑपरेशन धीरे-धीरे मीडिया से गायब होता चला गया। फिर एक दिन ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह अचानक शुरू हुआ था, उतनी ही चुप्पी से वह थम भी गया। इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा करना यहां जरूरी है। कहा जा रहा कि संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने भारत से मानवाधिकारों को लेकर जवाबदेही की मांग की। अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत से 'संवेदनशीलता' बरतने की अपील की। बात देश के भीतर की कि जाये तो ऑपरेशन के चलते स्थानीय जनता में असंतोष बढ़ने लगा था। स्कूल, कॉलेज बंद होने लगे थे और एक बार फिर घाटी में सुधरते हुए के हालात बिगड़ने लगे थे। मोदी सरकार को आगामी चुनावों में उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम मतों को प्रभावित करने की चिंता थी। किसी भी प्रकार की कठोर सैन्य कार्रवाई इस वर्ग को और अलग-थलग कर सकती थी। सूत्रों के अनुसार, ऑपरेशन की रणनीति को लेकर रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच मतभेद थे। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना था कि यह समय पूर्ण सैन्य कार्रवाई का नहीं, बल्कि सूक्ष्म कूटनीतिक प्रयासों का था।

बहरहाल, वजह कोई भी हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की छवि एक

'निर्णायक और मजबूत नेता' की रही है। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक उनके इस रूप की पुष्टि करते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का अचानक ठहर जाना इस छवि पर धुंध छा जाता है। समर्थकों को लगता है कि सरकार ने एक बार फिर "कठोर कदम" की शुरुआत करके अंत में 'यू-टर्न' ले लिया। यह एक राजनीतिक चाल अधिक और सुरक्षा नीति कम प्रतीत हुआ। वहीं अभी तक मोदी सरकार के साथ खड़ी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अब पूरे घटनाक्रम को 'राजनीतिक नौटंकी' करार देते हुए पूछ रहे हैं कि यदि ऑपरेशन जरूरी था तो उसे अधूरा क्यों छोड़ा गया? और यदि नहीं था, तो इसकी शुरुआत क्यों की गई? पूर्व सैनिकों और रक्षा विश्लेषकों ने भी यह सवाल उठाया कि जब सैनिकों को 'ऑपरेशन मोड' में लाया गया, तो क्या उन्हें केवल राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बनाया गया? उधर, सोशल मीडिया और जमीन पर जनता की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। एक ओर राष्ट्रवाद की भावना से भरपूर वर्ग ने इस ऑपरेशन के प्रति उत्साह दिखाया था, लेकिन जब यह बिना निष्कर्ष के थमा, तो वही वर्ग निराश हो गया। दूसरी ओर, शांति और संवाद की वकालत करने वालों ने राहत की सांस ली, पर यह असमंजस बना रहा कि सरकार ने अंततः क्या निर्णय लिया और क्यों। ऑपरेशन सिंदूर की खबरें जब आई तो प्रमुख चैनलों ने इसे मिशन कश्मीर 2.0 की संज्ञा दी। पैनल चर्चाओं में राष्ट्रवाद की लहरें उठीं, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन पर कोई आधिकारिक सूचना आनी बंद हुई, मीडिया ने भी चुप्पी साध ली। इससे यह संदेह और गहरा हुआ कि कहीं यह एक प्रायोजित प्रचार तो नहीं था।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक प्रतीक बन गया है उस नीति का, जो न तो पूरी तरह सैन्य थी और न ही पूरी तरह कूटनीतिक। इसकी अधूरी परिणति ने यह दिखा दिया कि केवल आक्रामक भाषण और प्रतीकात्मक नामों से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर इस अधूरे ऑपरेशन ने निश्चित रूप से असर डाला है, विशेषकर उस वर्ग में जो उन्हें निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक मानता रहा है। आने वाले चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी इस 'हिचकिचाहट' को छिपा पाने में सफल रहते हैं, या यह उनके राजनीतिक विपक्ष के लिए एक नया हथियार बन जाता है।●

● **अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)**

भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसा मौलिक अधिकार है, जो नेताओं को अपनी बात कहने का अवसर देता है। लेकिन जब यही स्वतंत्रता जिम्मेदारी से अलग होकर घमंड, असंवेदनशीलता और तुच्छ राजनीतिक लाभ का औजार बन जाए, तब यह न केवल लोकतंत्र की आत्मा को घायल करती है, बल्कि देश की एकता और संस्थानों की गरिमा पर भी प्रहार करती है। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे ही बयान सामने आए हैं, जो न केवल राजनीतिक मर्यादा की सीमा लांघते हैं, बल्कि उन संस्थाओं को भी घसीट लाते हैं, जिन्हें राजनीति से ऊपर माना जाता है खासकर देश की सेना।

मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह ने एक चुनावी सभा में सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की, वह शर्मनाक ही नहीं, बल्कि निंदनीय भी है। उन्होंने सेना में सेवा दे रहीं एक सम्मानित अधिकारी को आतंकवादी की बहन कह डाला। यह शब्द महज राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस मानसिकता का परिचायक था, जिसमें सत्ता की ललक नैतिकता को कुचल देती है। सोफिया कुरैशी, जिन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभियानों में भारत का नेतृत्व किया है, उनके लिए इस तरह के शब्द एक पूरे सैन्य समुदाय के मनोबल पर कुठाराघात हैं। यह केवल एक अफसर नहीं, बल्कि उस महिला की भी बेइज्जती है, जो भारत की सीमाओं की सुरक्षा में दिन-रात तैनात है। इस बयान के बाद देशभर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग उठाई। कांग्रेस,

आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की सोच करार देते हुए पूरे प्रकरण पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। वहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी कटघरे में खड़ा किया गया कि क्या वे अपनी कैबिनेट के मंत्री की इस स्तरहीन भाषा से सहमत हैं? लेकिन इससे भी अधिक गंभीर बात यह थी कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस बयान पर कोई ठोस कार्यवाही देखने को नहीं मिली। बयानबाजी की राजनीति में मानवीय गरिमा, संस्थागत सम्मान और संवैधानिक मर्यादा को ताक पर रख देना आज के समय की सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदी बन चुकी है। इसी बीच एक और विवाद खड़ा हुआ जब मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने एक सभा में यह कह दिया कि 'पूरा देश और सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है।' यह कथन न केवल अतिशयोक्ति से भरा

हुआ था, बल्कि यह सीधे-सीधे भारतीय सेना की स्वायत्तता और गरिमा पर हमला था। सेना एक संवैधानिक संस्था है, जो न किसी दल की है, न किसी व्यक्ति की। वह केवल राष्ट्र की है। उसका समर्पण संविधान, राष्ट्र और उसकी अखंडता के प्रति है किसी नेता या सरकार के प्रति नहीं। इस तरह की तुलना, जिसमें सेना को एक राजनीतिक व्यक्तित्व के अधीन बताया जाता है, गहरी चिंता का विषय है। विपक्ष ने इस पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भाजपा अपनी 'व्यक्ति पूजा' की राजनीति में सेना जैसे पवित्र संस्थान को भी लपेटने से नहीं चूकती।

उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक बयानबाजी ने नई हदें पार कीं जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जातिसूचक टिप्पणी की। उन्होंने सार्वजनिक मंच से उन्हें 'चमार' कहकर संबोधित किया। यह टिप्पणी न केवल अभद्र और अपमानजनक थी, बल्कि यह सामाजिक ताने-बाने को भी छिन्न-भिन्न करने वाली थी। एक तरफ तो दलित समुदाय को सम्मान देने की बात होती है, दूसरी ओर जब एक महिला अधिकारी जिसने अपनी मेहनत, योग्यता और साहस के दम पर एक अहम पद हासिल किया है को केवल उसकी जाति के आधार पर संबोधित किया जाता है, तो यह जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका प्रमाण बन जाता है। इस बयान ने समाज के भीतर जातिगत द्वंद्व को फिर से सतह पर ला खड़ा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सेना और समाज दोनों का अपमान करार दिया। भाजपा के कई अन्य नेताओं ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं, रामगोपाल यादव ने बाद में सफाई दी कि उन्होंने ऐसा किसी दुर्भावना से नहीं कहा, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या इतने वरिष्ठ नेता को यह नहीं पता कि

सार्वजनिक मंच से जातिसूचक शब्द कहना सामाजिक और संवैधानिक दोनों स्तरों पर अपराध है? क्या राजनीति की भाषा इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि उसमें न महिला सम्मान बचा है, न जातीय समरसता और न ही संस्थागत मर्यादा? इन तीनों घटनाओं में एक बात समान है नेताओं की गैर जिम्मेदाराना भाषा, सस्ती लोकप्रियता की

भूख, और संवैधानिक संस्थाओं का बार-बार अपमान। यह स्थिति केवल एक दल विशेष की नहीं, बल्कि आज की संपूर्ण राजनीति का दर्पण बन गई है। सेना, जो हमेशा राजनीतिक टकरावों से दूर रही है, उसे भी आज बयानबाजी की जंग में खींचा जा रहा है। यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है, बल्कि यह उस राष्ट्र भावना का भी क्षरण है, जिस पर भारत की पहचान टिकी हुई है।

यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल अपने नेताओं को केवल चुनाव जिताने वाली मशीनें न समझें, बल्कि उन्हें संवैधानिक जिम्मेदारी, भाषा की मर्यादा और सामाजिक संतुलन का पाठ पढ़ाएं। चुनाव आयोग को भी ऐसे बयानों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कठोर निर्देश और दंड का प्रावधान करना चाहिए ताकि यह संदेश स्पष्ट हो जाए कि कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसे भी चाहिए कि वह टीआरपी की दौड़ में इन बयानों को सनसनी की तरह परोसने के बजाय इन पर सार्थक बहस करे और जवाबदेही तय करने में भूमिका निभाए। जनता को भी अब यह तय करना होगा कि वह किन नेताओं को मंच दे रही है। क्या वे ऐसे लोगों को संसद और विधानसभाओं में भेज रही है जो सेना का अपमान करते हैं, महिलाओं को नीचा दिखाते हैं और जातिगत जहर फैलाते हैं? या फिर वे उन नेताओं को चुन रही है जो राष्ट्रहित, संविधान और सामाजिक समरसता को सर्वोपरि मानते हैं? क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट होती है और यदि वोट देने वाला जागरूक है, तो कोई भी नेता देश की गरिमा से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए, अब समय आ गया है कि देश के राजनीतिक विमर्श में मर्यादा, नैतिकता और उत्तरदायित्व फिर से स्थापित किया जाए। सेना को सेना रहने दिया जाए, राजनीति को राजनीति, और समाज को इंसानियत का आईना। यदि यह संतुलन नहीं बना, तो बयानबाजियों का यह जहर धीरे-धीरे लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर देगा और तब उसका इलाज किसी कोर्ट, आयोग या मीडिया के पास नहीं होगा। ●

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार , लखनऊ)

उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल के दिनों में जिस तरह की तीखी बयानबाजी और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली बहसों ने तूल पकड़ा है, उसमें सबसे हालिया और विवादास्पद मामला समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल द्वारा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी है। यह मामला न सिर्फ एक राजनीतिक टकराव का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि किस प्रकार डिजिटल युग में राजनीतिक दलों की ओर से किए गए पोस्ट सीधे सामाजिक सौहार्द, नैतिक मर्यादा और राजनीतिक विमर्श की गरिमा पर असर डाल सकते हैं। 16 मई को सपा मीडिया सेल के एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें बृजेश पाठक के डीएनए पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस पोस्ट में उपमुख्यमंत्री की तुलना सोनागाछी और जीबी रोड जैसे देश के रेड लाइट एरिया से जोड़ते हुए यह कहा गया कि उनका डीएनए इन क्षेत्रों में नियमित रूप से आने वाले लोगों से मिलाया जाना चाहिए, ताकि उनकी वास्तविक पहचान सामने आ सके। पोस्ट में जिस प्रकार के शब्दों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया, वह न केवल

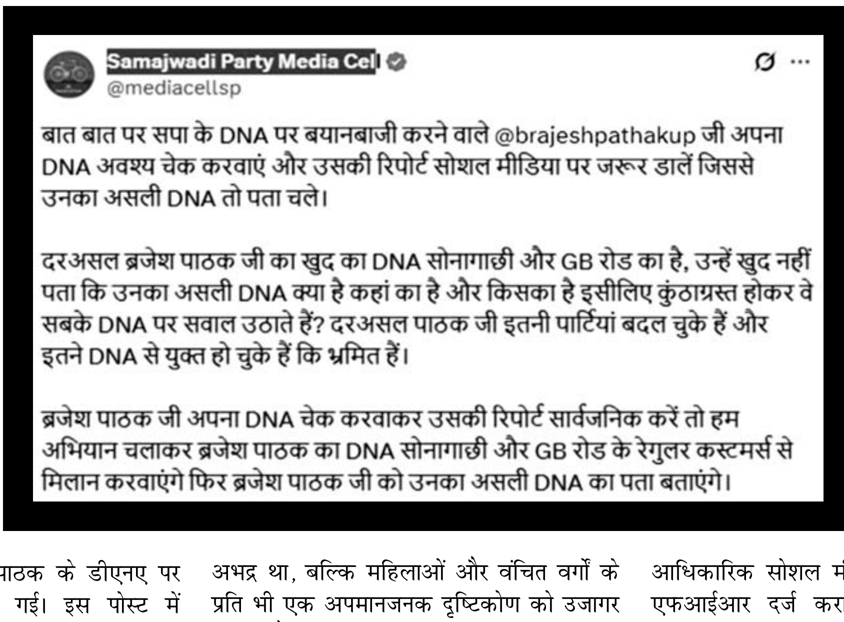
Samajwadi Party Media Cell
@mediacellsp

बात बात पर सपा के DNA पर बयानबाजी करने वाले @brajeshpathakup जी अपना DNA अवश्य चेक करवाएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें जिससे उनका असली DNA तो पता चले।

दरअसल ब्रजेश पाठक जी का खुद का DNA सोनागाछी और GB रोड का है, उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली DNA क्या है कहां का है और किसका है इसीलिए कुंठाग्रस्त होकर वे सबके DNA पर सवाल उठाते हैं? दरअसल पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने DNA से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित हैं।

ब्रजेश पाठक जी अपना DNA चेक करवाकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें तो हम अभियान चलाकर ब्रजेश पाठक का DNA सोनागाछी और GB रोड के रेगुलर कस्टमर्स से मिलान करवाएंगे फिर ब्रजेश पाठक जी को उनका असली DNA का पता बताएंगे।

अभद्र था, बल्कि महिलाओं और वंचित वर्गों के प्रति भी एक अपमानजनक दृष्टिकोण को उजागर करता है। यही कारण था कि इस पोस्ट को लेकर तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई और बृजेश पाठक ने स्वयं इसे अपनी दिवंगत माता-पिता का अपमान बताते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सार्वजनिक रूप से पूछा कि क्या यही उनकी पार्टी की भाषा है। बृजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस स्तर की मानसिकता का परिचय इस पोस्ट के माध्यम से दिया है, वह न केवल स्त्री विरोधी है बल्कि पतित सोच को भी दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में विचारों का विरोध होता है, लेकिन किसी के चरित्र और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर इस तरह के व्यक्तिगत हमले करना राजनीति को गटर में ले जाने जैसा है। उन्होंने अखिलेश यादव से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या यह उनकी पार्टी की अधिकृत नीति है या किसी असंतुलित व्यक्ति की निजी राय, जिसे पार्टी ने अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि समाजवाद के नाम पर सपा जिन बातों को बढ़ावा दे रही है, वह केवल गाली-गलौच, जातिगत विद्वेष और अनैतिक आचरण का पर्याय बन चुका है। इस पूरे मामले ने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी सक्रिय कर दिया। लखनऊ महानगर भाजपा अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने हजरतगंज थाने में समाजवादी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में यह कहा गया कि यह पोस्ट न केवल जातीय विद्वेष फैलाने वाली है, बल्कि महिलाओं का घोर अपमान करती है और समाज में आपसी सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करती है। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन करते हुए अखिलेश यादव का पुतला जलाया और समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस प्रकार की अभद्रता के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व

की ओर से कोई सार्वजनिक माफी नहीं मांगी जाती, तो वे आंदोलन तेज करेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से संयमित भाषा का प्रयोग करने को कहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि उपमुख्यमंत्री को भी अपनी भाषा और व्यवहार पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में यदि सत्ता पक्ष की ओर से निरंतर अनर्गल आरोप लगाए जाएंगे, तो विपक्षी कार्यकर्ताओं में भी प्रतिक्रिया की भावना उत्पन्न होगी। अखिलेश का यह बयान इस ओर इशारा करता है कि वे इस मामले में पूरी तरह सपा की सोशल मीडिया टीम के साथ खड़े हैं और उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि भाजपा को ऐसी टिप्पणियों से आपत्ति है तो उन्हें भी अपने नेताओं के बयानों की जांच करनी चाहिए।

बृजेश पाठक ने इसके जवाब में अखिलेश यादव पर एक बार फिर से तीखा प्रहार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाजवाद की प्रयोगशाला नहीं, बल्कि गाली-गलौच की प्रयोगशाला बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस डॉ. राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों को सपा अपनाने का दावा करती है, उनकी आत्मा इस तरह के कृत्यों से व्यथित होगी। पाठक ने यह भी कहा कि राजनीति में नैतिकता और शालीनता होनी चाहिए, लेकिन सपा नेतृत्व ने अब इसे पूरी तरह ताक पर रख दिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यदि विपक्षी दलों को लगता है कि सत्ता पक्ष की नीतियों में कोई त्रुटि है, तो उन्हें तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्तर पर जाकर अनर्गल आरोप लगाने चाहिए। यह प्रकरण न सिर्फ एक राजनेता के मान-सम्मान से जुड़ा है, बल्कि यह पूरे लोकतंत्र की परिपक्वता पर भी सवाल खड़ा करता है। सोशल मीडिया आज राजनीति का एक अत्यंत प्रभावशाली मंच बन चुका है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक दलों की ओर से इस मंच का उपयोग अब मर्यादाहीन और असंयमित भाषा के लिए किया जा रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। यह केवल एक दल या एक नेता का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक विमर्श की गिरती गुणवत्ता का प्रमाण है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में स्वस्थ आलोचना

सेवा में,

श्रीमान थाना प्रभारी,

थाना - हजरतगंज

जनपद लखनऊ।

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 16 मई 2025 को Samajwadi Party Media Cell (@mediacellsp) द्वारा ट्विटर (एक्स) अकाउंट से एक अत्यंत आपत्तिजनक, अभद्र, और मर्यादाहीन पोस्ट की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक जी के बारे मे अश्लील भाषा, अनर्गल आरोप, और मानसिक प्रताड़ना देने वाली बाते कही गई है। इस पोस्ट का उद्देश्य उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करना तथा उनकी छवि को ठेस पहुँचाना है। जो बाते लिखी गई है उन बातो से उप मुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक जी के आदरणीय माता जी और पिता जी के बारे मे भी बहुत गलत बोला गया है। पोस्ट मे प्रयुक्त भाषा – जैसे कि "GB रोड", आदि – अत्यंत घिनौनी, अपमानजनक और मानहानिकारक है। यह न केवल एक जनप्रतिनिधि पर सीधा हमला है, बल्कि पूरे संवैधानिक मूल्यो की अवहेलना भी है। समाजवादी मीडिया सेल ने ऐसा मर्यादाहीन पोस्ट/ट्वीट करके सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया है जिससे न केवल उप मुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक जी की छवि धूमिल हुई है साथ ही साथ इस प्रदेश की लोकतंत्रता को भी धूमिल कर दिया है।

उक्त ट्वीट/पोस्ट का URL https://x.com/mediacellsp/status/1923396626321920161?t=xnvfBjcY3dccAbK19PstgQ&s=19 और उक्त ट्वीट/पोस्ट की एक छायाप्रति इसस पत्र के संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण मे तत्काल प्रभाव से ट्विटर हैंडल @mediacellsp तथा संबंधित व्यक्तियो के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कर अविलम्ब उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

लखनऊ

प्रार्थी

एक अनिवार्य तत्व होती है, लेकिन जब यह आलोचना निचले स्तर पर जाकर निजी जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि और जातिगत पहचान पर केंद्रित हो जाए, तो इससे न केवल राजनीतिक वातावरण दूषित होता है, बल्कि आम जनता के बीच भी राजनीति के प्रति विश्वास में गिरावट आती है। इस घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों को अपने सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए केवल तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि वैचारिक परिपक्वता और सामाजिक जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना चाहिए। यह आवश्यक है कि सोशल मीडिया टीमों को केवल पार्टी लाइन का प्रचार करने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया जाए कि भाषा की मर्यादा और समाज की संवेदनाओं का आदर किस प्रकार किया जाता है। इस दिशा में अगर सख्ती नहीं बरती गई, तो आने वाले समय में राजनीतिक संवाद केवल ट्रोल संस्कृति में सिमटकर रह जाएगा। साथ ही यह मामला महिलाओं के प्रति सम्मान और सामाजिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से पोस्ट में रेड लाइट क्षेत्रों और वहाँ काम करने वाली महिलाओं को उपहास का माध्यम बनाया गया, वह स्त्री विरोधी मानसिकता की ओर इशारा करता है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात करने वाले दल यदि इस प्रकार की अभद्रताओं को संरक्षण देते हैं, तो यह न केवल पाखंड है बल्कि उस समावेशी समाज के खिलाफ एक सीधा प्रहार है जिसकी कल्पना संविधान करता है।

आखिरकार यह पूरा विवाद इस बात की ओर संकेत करता है कि भारतीय राजनीति को अब विचारधारा की बजाय ट्रोलिंग और बदजुबानी के रास्ते पर धकेला जा रहा है। यह जरूरी है कि देश के सभी राजनीतिक दल, चाहे वे सत्ता में हों या विपक्ष में, इस प्रवृत्ति पर गंभीर आत्ममंथन करें। राजनीतिक विमर्श को गरिमामय बनाना केवल भाषणों और घोषणाओं से नहीं होगा, बल्कि वह नेताओं और उनके संगठनों की वास्तविक नीयत और कार्यशैली से प्रकट होगा। अगर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह संभावना प्रबल है कि राजनीति में वैचारिक संघर्ष के स्थान पर व्यक्तिगत अपमान और नैतिक पतन ही मुख्य हथियार बन जाएंगे। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत होगा और इसका दुष्परिणाम देश की जनता को ही भुगतना पड़ेगा।●

राष्ट्रवाद के दौर में राहुल की जातिवादी राजनीति

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है और इस दौर के केंद्र में इस बार राहुल गांधी हैं। जब पूरा देश 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद राष्ट्रवाद की राजनीति की ओर फिर से झुक गया, राहुल गांधी ने इसके ठीक उलट जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय को अपनी राजनीतिक प्राथमिकता बना लिया है। यह वही बिहार है, जिसने कभी मंडल राजनीति की नींव रखी थी और जहां जातीय समीकरण अब भी हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का यह फोकस न केवल एक रणनीतिक चुनावी दांव है, बल्कि यह संकेत भी है कि कांग्रेस अब केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति की नब्ज पर भी हाथ रखना चाहती है।

बीते पांच महीनों में राहुल गांधी बिहार के चार दौरे कर चुके हैं और हर बार उन्होंने अलग-अलग जिलों को चुना है। यह चयन यूं ही नहीं है, बल्कि हर दौरे के पीछे सामाजिक समूहों की स्पष्ट गणना है। दरभंगा में उन्होंने दलित छात्रों से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अंबेडकर छात्रावास में जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पदयात्रा शुरू की, पुलिस और प्रशासनिक अफसरों से बहस की और आखिरकार टाउन हॉल में शिक्षा न्याय संवाद के जरिए अपनी बात रखी। यह कोई साधारण राजनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि प्रतीकों से भरा हुआ एक बड़ा संदेश था। राहुल गांधी ने दरभंगा में छात्रों से कहा कि देश की 90 फीसदी आबादी के पास कोई अवसर नहीं है। उन्होंने पूछा कि उच्च नौकरशाही में आपके कितने लोग हैं? डॉक्टरी पेशे में आपके कितने लोग हैं? शिक्षा व्यवस्था में आपके कितने लोग हैं? और फिर खुद ही जवाब दिया "जीरो"। उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा की सूची में मजदूरों की संख्या देखिए, वह 90 प्रतिशत आबादी से ही भरी हुई है। लेकिन जब बात सत्ता, संपत्ति और ठेकेदारी की आती है, तो सारा पैसा केवल 8 से 10 प्रतिशत लोगों के पास पहुंच

जाता है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विफलता बताया और कहा कि जब तक सामाजिक रूप से वंचित वर्ग एकजुट नहीं होंगे, तब तक कोई बदलाव संभव नहीं है। राहुल गांधी की यह बात बिहार जैसे राज्य में खास असर डाल सकती है, जहां जातीय आधार पर लोगों की पहचान और उनकी सामाजिक स्थिति गहराई से जुड़ी हुई है। खास बात यह भी है कि राहुल गांधी केवल भाषणों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने दलित समाज के साथ वक्त बिताने और उनकी संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। पटना के एक मॉल में उन्होंने दलित समाज के लोगों के साथ 'फुले' फिल्म देखी, जो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा फुले के जीवन पर आधारित है। यह एक संदेश था कि कांग्रेस अब दलित राजनीति को केवल चुनावी गणित नहीं, बल्कि वैचारिक जिम्मेदारी मान रही है।

हालांकि, राहुल गांधी का यह अभियान राजनीतिक टकराव से अछूता नहीं रहा। दरभंगा दौरे के दौरान पुलिस प्रशासन ने उन्हें छात्रावास में प्रवेश से रोका, जिसे कांग्रेस ने दलितों से संवाद रोकने की साजिश करार दिया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर इसे दलित विरोधी रवैया बताते हुए बिहार सरकार पर हमला किया और लिखा कि अगर एक नेता दलित छात्रों से मिलना चाहता है तो उसमें क्या गलत है? दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि भारत में कहीं भी छात्रावासों में राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती, इसलिए उन्हें टाउन हॉल में अनुमति दी गई थी। बिहार में कांग्रेस की यह सक्रियता महज बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सहयोगी दल आरजेडी के लिए भी चुनौती बनती जा रही है। दरअसल, जिस प्रकार से राहुल गांधी सीधे तौर पर दलित-पिछड़े वर्ग को संबोधित कर रहे हैं, उससे आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक खिसक सकता है। यही कारण है कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस अब आरजेडी को भी राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंद्वी मानने लगी है। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, बिहार में आरजेडी पर कांग्रेस की निगाह टिकी है।

लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और आरजेडी की स्थिति लगभग बराबर रही। लेकिन यह बराबरी कई समीकरणों पर आधारित थी, जैसे पप्पू यादव का कांग्रेस के समर्थन में खड़ा होना। अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, कांग्रेस शायद खुद को आरजेडी की छाया से निकालकर स्वतंत्र ताकत के रूप में स्थापित करना चाहती है। यही वजह है कि राहुल गांधी के कार्यक्रमों में जातिगत न्याय, सामाजिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे बार-बार

सामने आते हैं, जो कि आरजेडी की पारंपरिक राजनीति का मूल आधार रहे हैं। राहुल गांधी लगातार यह भी कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जातिगत जनगणना को लेकर दबाव में आई और उन्हें अंततः इसे स्वीकार करना पड़ा। कांग्रेस इसे अपनी जीत के रूप में प्रचारित कर रही है और राहुल गांधी बार-बार दोहरा रहे हैं कि जब तक समाज की सही तस्वीर हमारे पास नहीं होगी, तब तक न्याय संभव नहीं है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि निजी संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए और एससी-एसटी सब-प्लान का बजट पारदर्शी ढंग से लागू हो। बीजेपी की रणनीति इस पूरे परिदृश्य में अलग है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की भावना को फिर से जगाने की कोशिश की जा रही है। इसका असर भी दिखा है, लेकिन बिहार में राहुल गांधी की जातीय राजनीति के सामने बीजेपी को भी अब जवाब देना पड़ रहा है। बीजेपी नेता बार-बार यह कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का क्रेडिट कांग्रेस नहीं ले सकती, क्योंकि इसे लागू करने का फैसला तो एनडीए सरकार ने किया है। फिर भी

राहुल गांधी लगातार इसे अपनी उपलब्धि के रूप में जनता के सामने रख रहे हैं। यह दिलचस्प है कि जब राहुल गांधी को दरभंगा में छात्रों से मिलने से रोका गया, उन्होंने इसे उसी तरह से प्रचारित किया जैसे उन्होंने लोकसभा में बोलने न दिए जाने की घटनाओं को किया था। उनका यह तरीका विपक्ष को एक पीड़ित की तरह पेश करने का है, जो कि सत्ताधारी दल के अहंकार और तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है। यह छवि जनता के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है, खासकर तब जब मुद्दा दलित या पिछड़े वर्ग से जुड़ा हो।

कुल मिलाकर, राहुल गांधी ने बिहार चुनावों के लिए एक ऐसी पिच तैयार की है, जो अब तक बीजेपी और आरजेडी दोनों से अलग है। वह खुद को सामाजिक न्याय के एक नए प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें उन्हें सीमित सफलता भी मिलती दिख रही है। अब यह देखना होगा कि बिहार की जनता इस नई कांग्रेस को कितनी गंभीरता से लेती है। क्या राहुल गांधी का जातीय न्याय का एजेंडा चुनाव में निर्णायक साबित होगा? क्या कांग्रेस आरजेडी को पछाड़कर प्रमुख विपक्ष बन पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वह जनाधार फिर से हासिल कर पाएगी जो कभी उसका हुआ करता था? बिहार की राजनीतिक बिसात पर बिछी यह चालें आने वाले दिनों में और रोचक मोड़ लेंगी, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ संसद तक सीमित नेता नहीं, बल्कि जमीनी संघर्ष करने वाले राजनीतिक खिलाड़ी भी हैं। उनकी यह कोशिश, चाहे सफल हो या असफल, भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे चुकी है एक ऐसी बहस जो सामाजिक न्याय को फिर से केंद्रीय मुद्दा बना रही है।●

पटना एलआईसी एचएफएल ने अवैध घोषित होटल के रेंट पर दिया करोड़ों का लोन

LIC HFL के रीजनल मैनेजर अक्षय कुमार साहू, उप रीजनल मैनेजर निपेंद्र कुमार दीक्षित और एरिया मैनेजर विनय कुमार सिंह ने तिरुपति होम्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक शशि भूषण सिन्हा के साथ मिलकर किया 11 करोड़ के फर्जी लोन का भुगतान

● शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला

भारत में विजय माल्या और नीरव मोदी सहित कई बड़े व्यवसायी ने बैंकिंग फ्रॉड कर आम जनता के पैसों का बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर बंदरबांट किया है। भारत ही नहीं विश्व के कई बैंक बैंकिंग फ्रॉड के कारण बंद हो गए हैं। आज भारत में 3 लाख से ऊपर के हाउसिंग लोन में फर्जीवाड़ा किया गया है, जिससे सभी अकाउंट एनपीए हो गए हैं। साल 2010 में LIC HFL में फर्जी लोन का मामला प्रकाश में आने के बाद सीबीआई जांच हुआ और कई बड़े अधिकारियों पर गाज भी गिरा था। सीबीआई ने इस घोटाले में LIC HFL के सीईओ रामचंद्र नायर सहित आठ अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया था। ताजा मामला पटना के किदवईपुरी में रेड वेलवेट नमक होटल से जुड़ा हुआ है। किदवई पुरी में पोस्टल को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड (नया नाम पोस्टल

कम अदर गवर्नमेंट एम्पलाई को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड) नामक एक समिति का गठन कर पोस्टल एवं अन्य सरकारी सेवकों के लिए रहने के उद्देश्य से आवासीय भू-खण्ड लिया गया, जिसपर सिर्फ आवासीय गतिविधियों की ही इजाजत दी गई। इस समिति के बॉयलॉज में लिखा गया है की पोस्टल एवं अन्य सरकारी सेवकों के लिए आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराया जाएगा तथा इसमें व्यावसायिक कार्यो की अनुमति नहीं होगी। इस समिति के भू-खण्ड का कुल क्षेत्रफल 1072.98 है और इसके 34.5 मीटर के भू-खण्ड पर तिरुपति होम्स लिमिटेड ने अतिथि गृह बनाने का फर्जी नक्शा जो रविवार दिनांक 24/05/2009 को पास कर के अतिथि गृह के जगह पर व्यावसायिक बहुमंजिला जिला होटल "होटल रेड वेलवेट" में तब्दील कर दिया, जिस पर पटना नगर निगम निगरानी मामला संख्या 1391/2014 किया गया। इस अवैध निर्माण के कारण बुद्धा कॉलोनी थाना में थाना कांड संख्या-231/2013, 238/2014 और 288/2014

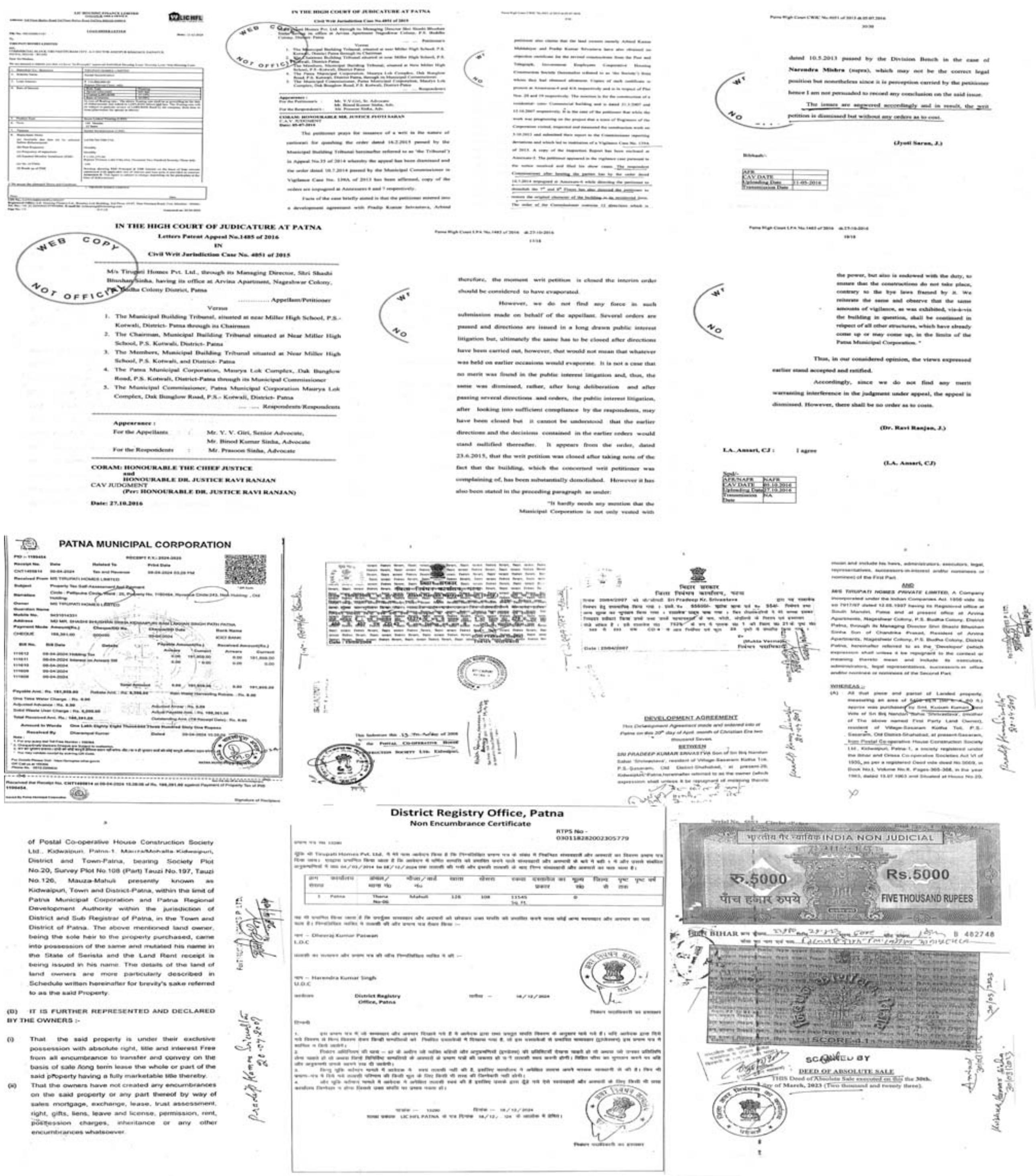

आपराधिक मामले दर्ज हैं। पटना उच्च न्यायालय में CWJC संख्या-4051/2015 और LPA नंबर-1485/2016 में इस निर्माण को अवैध घोषित किया गया है और इसके अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का स्पष्ट आदेश पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है।

इस जमीन का कोई टाइटल डीड भी तिरुपति होम्स प्राइवेट लिमिटेड के पास नहीं है। इस भूमि पर अवैध तरीके से डेवलपमेंट एग्रीमेंट के जरिए सिर्फ अतिथि गृह बनाने का एग्रीमेंट है। तिरुपति होम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शशि भूषण सिन्हा के ऊपर कई लोन विवाद भी चल रहा है। शशि भूषण सिन्हा के ऊपर पीएनबी में 6 करोड़ 20 लाख का सरफेसी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है और पटना उच्च न्यायालय के दखल के बाद लोन भुगतान हुआ है। इस भू-खण्ड पर कोई भी व्यावसायिक निर्माण पूरी तरह से अवैध है और यह सरकारी कर्मचारियों

Endorsement of Certificate of Admissibility

Endorsement under section 52

Endorsement under section 58

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

DEVELOPMENT AGREEMENT

Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 23)

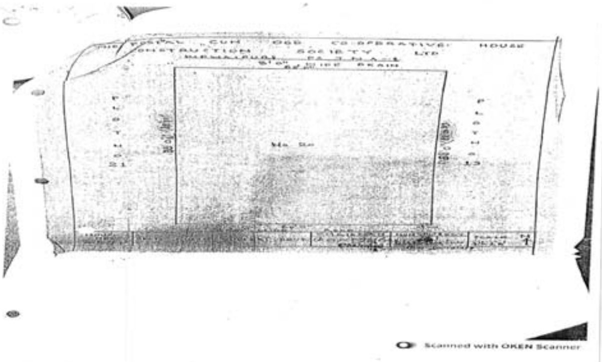

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

DEED OF ABSOLUTE SALE

आयकर विभाग INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार GOVT. OF INDIA

TIRUPATI HOMES LIMITED

12/05/1997

Permanent Account Number

AADCT7444H

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.13218 of 2019

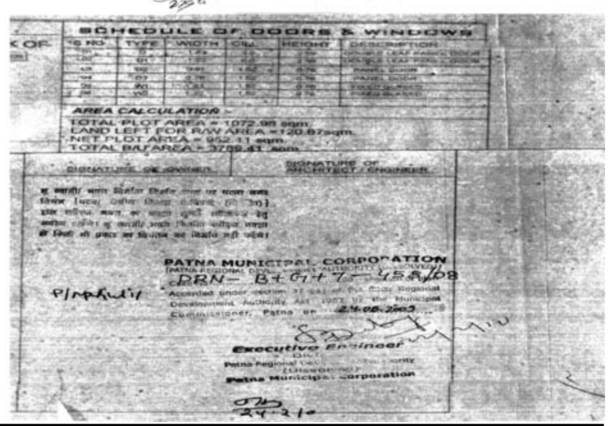
SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

AREA CALCULATION

PATNA MUNICIPAL CORPORATION

Executive Engineer

के मौलिक अधिकारों का हनन भी है। बावजूद LIC HFL के रीजनल मैनेजर अक्षय कुमार साहू, उप रीजनल मैनेजर निपेंद्र कुमार दीक्षित और एरिया मैनेजर विनय कुमार सिंह की जोड़ी ने LIC HFL लोन संख्या-9001020003343 के लिए 11 करोड़ रुपयों का लोन स्वीकृत कर दिया। विदित हो कि उक्त लोन पूर्व LIC HFL द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है, साथ ही एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी द्वारा भी इस लोन को अस्वीकृत किया जा चुका है। यही नहीं आवेदक के सिविल में करोड़ों रुपयों के लोन का राइट ऑफ और विलफुल डिफॉल्ट अंकित है, फिर भी आरबीआई और NHFC के नियम के विरुद्ध लोन स्वीकृत किया गया। जिस होटल के रेंटल सिक्यॉरिटाइजेशन (एलआरडी) पर लोन दिया गया। उसे पटना उच्च न्यायालय पटना और पटना नगर निगम द्वारा अवैध घोषित किया जा चुका

अक्षय कुमार साहु

निपेंद्र कुमार दीक्षित

विनय कुमार सिंह

है। लोन मुकदमा दर्ज है। लोन लेने के पहले बिहार सरकार से NEC भी नहीं लिया गया था। आवासीय भू-खण्ड पर व्यावसायिक निर्माण अपराध के श्रेणी में आता है और इसे पटना उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है। सबसे बड़ी बिडम्बना देखीये जिस रेड वेलवेट होटल के रेंट सिक्यॉरिटाइजेशन पर लोन दिया गया है, वह रेंट एग्रीमेंट मात्र 1000 रूपये के स्टांप पर बना हुआ है। मतलब इतने बड़े लोन देने से पहले इसे रजिस्ट्री भी करना जरूरी नहीं समझा गया और लोन की पूरी प्रक्रिया अतिशीघ्र पूरी कर ली गई। 1 वर्ष पूर्व जब लोन अस्वीकृत किया गया था तब लोन सोर्सिंग एजेंट द्वारा किया गया था, लेकिन इस बार लोन डायरेक्ट किया गया। LIC HFL के रीजनल मैनेजर अक्षय कुमार साहू, उप रीजनल मैनेजर निपेंद्र कुमार दीक्षित और एरिया मैनेजर विनय कुमार सिंह ने तिरुपति होम्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक शशि भूषण सिन्हा के साथ मिलकर 11 करोड़

के फर्जी लोन में करोड़ों रुपयों की उगाही की है। पूरे मामले को देखने से साफ पता चलता है कि यह लोन स्पष्ट तौर पर बिना पैसा लिए नहीं किया गया है फिर भी LIC HFL के बड़े-बड़े अधिकारी मौन साधे हुए हैं। कई आवेदन LIC HFL के हेड क्वार्टर तथा अन्य सभी संबंधित जगहों पर दिया गया लेकिन पैसा तो ऊपर तक पहुंचता है इसलिए LIC HFL के सीईओ सहित कोई भी अधिकारी इसमें कोई भी कार्रवाई करने से बचते आ रहे हैं।

आज किसी ईमानदार आदमी को लोन की जरूरत हो तो बैंकों द्वारा इतने पेपर मांगे जाते हैं कि आदमी थक-हारकर साहूकार से मोटे ब्याज दर पर पैसा उठाने के लिए विवश हो जाता है, लेकिन जब आदमी के पास पहुँच और पैसा हो तो लोन आसानी से मिल जाता है, इसका नमूना यह लोन है। पैसा हो तो लोन आसानी से मिल जाता है, चाहे सिविल कितना भी खराब क्यों ना हो इस लोन में तिरुपति होम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शशि भूषण सिन्हा का सिबिल स्कोर खराब है। उनके सिबिल स्कोर में कई राइट ऑफ और विलफुल था, उसके साथ ही सरफरेसी एक्ट का भी मुकदमा था, बावजूद एक सप्ताह के अंदर 11 करोड़ का लोन दे दिया गया।

आज भारत के कई बैंक LIC HFL के तरह अधिकारियों के तरह माफियाओं से मिलकर इसी तरह से लोन बांट रहे हैं, जिससे भारत में लाखों-करोड़ों अकाउंट एनपीए हो गया है। LIC HFL में जो 5 लाख का भी लोन लेता है। डिफॉल्ट होने पर घर पर पोस्टर चिपकाए जाता है और खुद जब लोन देने वाला गलत है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने वाला आज कोई नहीं है, क्योंकि LIC HFL में पैसे का बंदरबाँट किया जा रहा है। कभी-कभी बड़े व्यवसाईयों को देखकर बंदरबाँट किया जा रहा है। कभी छोटे व्यावासियों को देखकर बंदरबाँट किया जा रहा है। आज अगर आपका बैंक बंद हो जाता है तो मात्र भारत सरकार द्वारा 5 लाख की सिक्योरिटी दी जाती है। इसका मतलब हुआ कि आपके बैंक में आपके खाते में करोड़ों रुपया है, लेकिन आपको भारत सरकार से सिक्योरिटी के रूप में मात्र 500000 रूपये का भुगतान किया जाएगा। अगर समय रहते इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं किया गया तो आज नहीं तो कल LIC HFL को भी बंद होते देर नहीं लगेगी। ●

नियमों को ताख पर और पैसे का वजन देखकर करते हैं सुरक्षा एजेंसियों के निविदा का निपटारा

● शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला

आज के दौर में जहाँ देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, वहीं सुरक्षा एजेंसियों के टेंडर प्रक्रिया में हो रही धांधली एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। टेंडर यानी निविदा प्रक्रिया वह प्रणाली है जिसके माध्यम से सरकार या किसी संगठन द्वारा आवश्यक सेवाओं या वस्तुओं की खरीदारी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाती है, लेकिन जब यह प्रक्रिया ही भ्रष्टाचार और मिलीभगत की भेंट चढ़ जाए तो देश की सुरक्षा पर सीधा खतरा उत्पन्न हो जाता है और साथ ही उस संस्थान के सुरक्षा पर सीधा खतरा उत्पन्न हो जाता है। आज सुरक्षा एजेंसियों के निविदा में पहले ही तय कर लिया जाता है कि निविदा किसको देना है। इसके लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, सुरक्षा प्रमाण पत्र और तकनीकी योग्यता दिखाकर निविदा अवार्ड कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि निविदा का मानदंड ही इस प्रकार बनाए जाते हैं कि एक विशेष कंपनी ही योग्य मानी जाती है और ऐसी सुरक्षा एजेंसियां निविदा जीतने के बाद अक्सर सस्ते और घटिया क्वालिटी के उपकरण मुहैया कराती है साथ ही अनुभवहीन कर्मियों की नियुक्ति करती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। आज जरूरत है की सुरक्षा एजेंसियों के टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं बल्कि उस संस्थान की सुरक्षा और नागरिकों के जीवन रक्षा के लिए भी जरूरी है। जब तक इस प्रक्रिया को सख्ती से नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक सुरक्षा केवल एक शब्द बनकर रह जाएगा। आजकल निजी सुरक्षा एजेंसियों के आधे कर्मचारी उस संस्थान के बड़े अधिकारियों के राज-दरबार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। आज बिहार के सबसे बड़े पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) के अधीक्षक डॉ. इंद्रशेखर

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited

BMSICL

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited

BMSICL

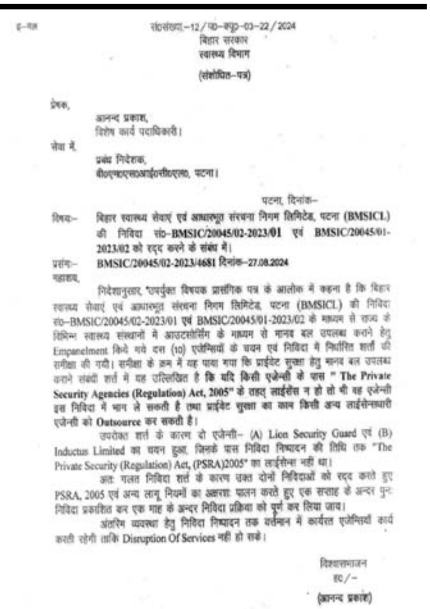
ई-मेल

सं०संख्या-12/प०-क्यू०-03-22/2024
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
(संशोधित-पत्र)

प्रेषक,
आनन्द प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,
प्रबंध निदेशक,
बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय- बिहार स्वास्थ्य सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना (BMSICL) की निविदा सं०-BMSIC/20045/02-2023/01 एवं BMSIC/20045/01-2023/02 को रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग- BMSIC/20045/02-2023/4681 दिनांक-27.08.2024

महाशय,

निदेशानुसार, "उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि बिहार स्वास्थ्य सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना (BMSICL) की निविदा सं०-BMSIC/20045/02-2023/01 एवं BMSIC/20045/01-2023/02 के माध्यम से राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल उपलब्ध कराने हेतु Empanelment किये गये दस (10) एजेन्सियों के चयन एवं निविदा में निर्धारित शर्तों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्राईवेट सुरक्षा हेतु मानव बल उपलब्ध कराने संबंधी शर्त में यह उल्लिखित है कि यदि किसी एजेन्सी के पास " The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005" के तहत् लाईसेंस न हो तो भी वह एजेन्सी इस निविदा में भाग ले सकती है तथा प्राईवेट सुरक्षा का काम किसी अन्य लाईसेन्सधारी एजेन्सी को Outsource कर सकती है।

उपरोक्त शर्त के कारण दो एजेन्सी- (A) Lion Security Guard एवं (B) Inductus Limited का चयन हुआ, जिनके पास निविदा निष्पादन की तिथि तक "The Private Security (Regulation) Act, (PSRA)2005" का लाईसेन्स नहीं था।

अतः गलत निविदा शर्त के कारण उक्त दोनों निविदाओं को रद्द करते हुए PSRA, 2005 एवं अन्य लागू नियमों का अक्षरशः पालन करते हुए एक सप्ताह के अन्दर पुनः निविदा प्रकाशित कर एक माह के अन्दर निविदा प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाय।

अंतरिम व्यवस्था हेतु निविदा निष्पादन तक वर्तमान में कार्यरत एजेन्सियाँ कार्य करती रहेंगी ताकि Disruption Of Services नहीं हो सके।

विश्वासभाजन
ह०/-
(आनन्द प्रकाश)

Intelligence Security of India

पत्रांक: ISI/२०२५ दिनांक 12.04.2025

सेवा में, निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, बेली रोड, पटना।

BMSICL

BMSICL

ठाकुर को दो-दो बार विभागीय कार्रवाई लंबित रहते हुए सरकारी नियमों को ताख पर रखकर सेवा विस्तार दिया गया। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आईजीआईएमएस के अधीक्षक मनीष मंडल को NMC नियमों को ताख पर रखकर पिछले कई सालों से आईजीआईएमएस का अधीक्षक बनाया गया है। इन दोनों संस्थान के अधीक्षक बनाए जाने के पीछे एक ही मकसद है-इन लोगों को भ्रष्टाचार में छूट देकर उनका बड़ा हिस्सा मंत्री और बड़े अधिकारियों तक पहुंचाना। दोनों अधीक्षक गाहे-बगाहे यह दावा करते हैं कि हमने मुख्यमंत्री आवास को भी मैनेज कर रखा है और यह उनकी कार्य शैली से भी दिखता है। यह सीधे-सीधे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ईमानदार चरित्र को भी दागदार करने का प्रयास करता है।

आईजीआईएमएस के वॉच और वार्ड सर्विस के लिए दो निविदा यूनिट A और यूनिट B निकाली गई। दोनों निविदा निकाले जाने का उद्देश्य था कि की विपरीत परिस्थितियों में कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। हम केवल सच के इस अंक में यूनिट B के निविदा में हुई धांधली की बात कर लेते हैं, अगले अंक में यूनिट A में हुए भ्रष्टाचार की बात कर लेंगे। यूनिट B के लिए प्रकाशित निविदाओं के बोली में चार निविदाताओं ने भाग लिया, जिसमें दो निविदादाताओं की वित्तीय बोली समान पाई गई। बिहार सरकार के पत्रांक-M-4-6/2023/2988/B के अनुसार कोई भी निविदादाता का सर्विस चार्ज-3.85 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इस आदेश के आलोक में दोनों निविदाताओं ने अपनी बोली 3.85% रखी। मतलब दोनों ही L1 घोषित किए गए, लेकिन आईजीआईएमएस ने सिर्फ SIS को ही विजेता घोषित करते हुए उसे सुरक्षा एजेंसी का कार्य आवंटित कर दिया। विदित हो कि SIS के मालिक भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ॠतुराज सिन्हा और पिता पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा की कंपनी है और बिहार के स्वास्थ्य विभाग की कमान अभी मंगल पांडे के पास है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगना छोटी बात है। क्योंकि मंत्री जी के निजी सहायक भी खुलेआम कहते हैं कि पैसा दिल्ली तक देना होता है, इसलिए बिना पैसा का यहां कोई काम नहीं होता है। भाजपा के प्रभाव वाले विभाग में BFR, GFR और CVC नियमों की बात करना गुनाह के श्रेणी में

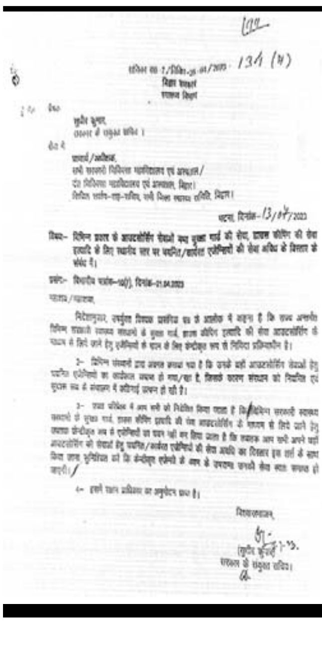

Intelligence Security of India

पत्रांक ISI/ 114 /25 दिनांक 04.02.2025

सेवा में, चिकित्सा अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना, बिहार।

अधीक्षक का कार्यालय

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

ज्ञापांक - 2935 पटना, दिनांक- 30/04/2022

निविदा सूचना

तकनीकि निविदा शर्त हेतु अनिवार्य शर्ते

1 निविदादाता को कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956/पार्टनरशिप एक्ट 1932/ इंडियन सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860/इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882/बिहार शॉप एण्ड इस्टैबिलिशमेन्ट एक्ट 1953 के तहत निविदा प्रकाशन के तिथि तक तीन वर्ष पूर्व से निबंधित होना होगा तदनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्वामित्व प्रमाण–पत्र एवं निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

2 निविदादाता को बिहार सरकार गृह (विशेष) विभाग के द्वारा The Private Security Agencies (Regulation) Act. 2005 (PSARA-2005) के तहत निबंधित होना होगा। तदनुकूल अद्यतन निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

3 निविदादाता को 1000 (एक हजार) बेड वाले सरकारी अस्पताल में तीन वर्षों का सेवानिवृत फौजी/अर्द्धसैनिक फौजी के साथ सफलतापूर्वक कार्य किये जाने का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा। तदनुकूल सक्षम प्राधिकार के द्वारा निविदा प्रकाशन की तिथि के पश्चात निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (अनुसूची–1 के रूप में निर्धारित विहित प्रपत्र में) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। एक ही अवधि में एक से अधिक संस्थानों में किये गये कार्य को समान रूप से प्राथमिकता देते हुए उक्त अवधि को भी कार्य अनुभव में जोड़ा जायेगा।

4 निविदादाता को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) एवं कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में निबंधित होना होगा। तदनुसार निविदा प्रकाशन से एक वर्ष पूर्व का 200 (दो सौ) कर्मियों का अंशदान की जमापर्ची (ECR) की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

5 निविदादाता को GST में निबंधित रहना अनिवार्य होगा। तदनुसार वित्तीय वर्ष (Financial Year) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 का वार्षिक टर्न ओवर के अनुरूप जी०एस०टी० रिर्टन का साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

6 निविदादाता को PAN Card एवं विगत तीन निर्धारण वर्ष (Assesment Year) 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का आयकर रिर्टन के साथ–साथ निबंधित चार्टर्ड अकाउटेंड द्वारा Audited Balance Sheet with Profit & Loss Account संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

7 निविदादाता को विगत तीन वित्तीय वर्ष (Financial Year) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के लिए 5,00,00,000–00 (पाँच करोड़) का औसत टर्न ओवर होना अनिवार्य होगा तदनुसार निबंधित चार्टर्ड अकाउटेंड द्वारा निर्गत Turn Over Certificate with UDIN के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

8 निविदादाता का संचालित चालु खाता (Current Account) से सबंद्ध कम से कम रू0–1,00,00,000–00 (एक करोड़) का Solvency Certificate (शोधन क्षमता प्रमाण–पत्र) संस्थान के नाम से मूलप्रति में सलग्न करना अनिवार्य होगा। जो निविदा प्रकाशन के तिथि के पश्चात् निर्गत होना आवश्यक होगा।

9 निविदादाता को निविदा अग्रधन राशि के रूप में रू0–10,00,000–00 (दस लाख) का बैंक ड्राफ्ट (जो अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना के नाम से देय होगा) जो तकनीकि निविदा के साथ संलग्न किया जायेगा। अग्रधन राशि संलग्न नहीं करने की

Page 2 of 7

स्थिति में निविदा स्वतः अस्वीकृत समझा जायेगा। MSME(Micro Small Medium Enterprises) / NSIC (National Small Industries Corporation) से निबंधित निविदादाता को नियमानुसार छुट अनुमान्य होगा।

10 निविदादाता को निविदा शुल्क के रूप में रू0–10,000–00 (दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट (जो अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना के नाम से देय होगा) तकनीकि निविदा के साथ संलग्न किया जायेगा। निविदा शुल्क संलग्न नहीं करने की स्थिति में निविदा स्वतः अमान्य माना जायेगा। जो Non-Refundable होगा। MSME/NSIC से निबंधित निविदादाता को नियमानुसार छुट अनुमान्य होगा।

11 निविदादाता को गुणवत्तायुक्त सेवा के लिए ISO 45001 : 2018 (Occupational Health and Safety Management Systems) एवं ISO 18788 : 2015 (Management Systems for Private Security Operations Requirements) द्वारा निबंधित होना होगा तथा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि तक वैध निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

12 निविदादाता को निविदा के साथ इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा कि फर्म/कंपनी/एजेंसी निबंधित संस्थान के Propriter / Director / Partner न्यायालय द्वारा किसी भी क्रिमनल केस में दोषी नहीं ठहराये गये है।

13 सिर्फ कम्प्युटर टंकित निविदा ही स्वीकार्य होगी। किसी भी परिस्थिति में हस्तलिखित/सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

14 निविदादाता को प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत निम्न आशय का शपथ–प्रमाण पत्र की मूल प्रति तकनीकि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आशय निम्नांकित है:–

(क) निविदा में वर्णित सभी शर्त्ते मुझे मान्य है।

(ख) मेरे प्रतिष्ठान को पूरे भारत वर्ष में किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है, तथा मेरे फर्म के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ग) मेरे प्रतिष्ठान को कभी भी किसी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी कागजात/दस्तावेज सही है। कालांतर में यदि कोई भी अभिलेख/दस्तावेज/ कागजात गलत/ फर्जी या छेड़–छाड़ आदि कर प्रस्तुत किये जाने का मामला प्रकाश में आता है तो अग्रधन राशि/Performance Security Deposit जब्त करते हुए मेरे विरूद्ध विधि सम्मत् कार्यवाही हेतु अस्पताल प्रशासन स्वतंत्र होगी।

15 क्रेता अधिकारी/क्रय समिति किसी भी निविदा जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है स्वीकार करने या बिना कारण बतायें किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए निविदादाताओं ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने का अधिकार को आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार करना बाध्यकारी नहीं होगा।

16 समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा पटना में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

17 करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Performance Security Deposit)

(क) अंतिम रूप से सफल निविदादाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराकर करार–पत्र का निष्पादन अपने खर्च पर करना होगा।

Page 3 of 7

आता है। बिहार सरकार के वित्त विभाग के पत्रांक संख्या-M-4-06/2023/2988/B दिनांक-13/03/2023 के पारा (iii) में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि निविदा यदि एक से अधिक निविदादाता का उद्धत (QUOTED) न्यूनतम सेवा शुल्क की दर समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदा का निष्पादन किया जाएगा तथा इस पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी कराई जाएगी। निविदा के निष्पादन की पूरी प्रक्रिया में बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन अपेक्षित होगा। फिर भी निविदा सिर्फ SIS को अलॉट करना संस्थान में ऋतुराज सिन्हा के प्रभाव को दिखाता है या यूं कहें नीतीश कुमार के इस दावे को भी झुठलाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। सिक्योरिटी एजेंसी आईएसआई ने आईजीएमएस के निदेशक को पत्र लिखकर न्याय संगत निर्णय लेते हुए संस्थान की गरिमा को बनाए रखते हुए न्यायपूर्ण निर्णय लेने का अनुरोध भी किया, लेकिन आईजीआईएमएस के अधीक्षक मनीष मंडल और शैलेंद्र कुमार सिंह के आगे तो संस्थान के निदेशक भी लाचार हैं।

स्वास्थ्य विभाग पत्रांक संख्या-10 (7) दिनांक- 21/04/2023 में सभी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि विभिन्न प्रकार के मैनपॉवर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लेने हेतु केंद्रीय रूप से निविदा प्रकाशित करने के निर्णय के आलोक में स्थानीय स्तर पर नई निविदा दाताओं के प्रकाशन सहित पूर्व प्रकाशित परंतु प्रकाशन अनिष्पादित निविदा के निष्पादन पर रोक लगाई जाए तथा जिन निष्पादित निविदा को कार्य आदेश निर्गत नहीं हुआ है उसे स्थगित रखा जाए। लेकिन इस आदेश को कई संस्थान ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और मनमानी करने लगे तो पुनः बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग पत्रांक संख्या-134 (7) दिनांक-23/07/2023 को एक पत्र लिखकर बिहार के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को कहा गया की विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं ने सुरक्षा गार्ड, हाउसकीपिंग इत्यादि की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिए जाने हेतु जब तक केंद्रीयकृत रूप से एजेंसियों का चयन नहीं कर लिया जाता है कि तब तक आप सभी अपने यहां आउटसोर्सिंग की सेवाओं हेतु चयनित कार्यरत एजेंसी की सेवा अवधि का विस्तार इस शर्त के साथ किया जाना सुनिश्चित करें कि केंद्रीयकृत एजेंसियों के चयन के उपरांत उनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। सरकार के इन दोनों महत्वपूर्ण पत्रों के बावजूद भी कई संस्थाओं ने अपनी मनमानी जारी रखी। जहां तक PMCH के अधीक्षक की बात है वह तो अपने आप को मुख्यमंत्री के करीबी ही समझते हैं। केंद्रीकृत निविदा निष्पादन करने वाली एजेंसी बीएमएसआईसीएल (BMSICL) के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र कुमार (भारतीय प्रशासनिक सेवा) ने अपने पत्रांक-BMSC/20045/02- 2023/1967, दिनांक-11/0/2024 को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र लिखकर कहा कि बीएमएसआईसीएल द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सभी संस्थाओं हेतु विभिन्न श्रेणी में मैनपॉवर आउटसोर्सिंग के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी EMPANELMENT के लिए E-Proc2 के माध्यम से प्रकाशित निविदा संख्या-BMSIC/20045/02-2023/01 एवं BMSIC/20045/02-2023/02 द्वारा चयनित 10 एजेंसियों के बीच कंप्यूटराइज्ड रेंडम एलोकेशन सिस्टम के माध्यम से जिलों का आवंटन किया गया, इसके पश्चात तद्नानुसार जिलावार संबंद्ध किए गए।

INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
SHEIKHPURA PATNA-14

(Autonomous Body under Department of Health, Government of Bihar)

NOTICE INVITING E-TENDER
FOR WATCH & WARD SERVICES
(UNIT-'B')

Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura, Patna-800014, Bihar
PHONE-0612-2297099/2297631; Website: www.igims.org

1

ITEM NO.64 COURT NO.8 SECTION XVI

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s). 12510/2025

[Arising out of impugned final judgment and order dated 04-04-2025 in CWJC No. 14739/2024 passed by the High Court of Judicature at Patna]

MS LION SECURITY GUARD SERVICES Petitioner(s)

VERSUS

THE STATE OF BIHAR & ORS. Respondent(s)

IA No. 112495/2025 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT, IA No. 112498/2025 - EXEMPTION FROM FILING O.T.

WITH
SLP(C) No. 12583/2025 (XVI)
IA No. 112894/2025 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT, IA No. 112895/2025 - EXEMPTION FROM FILING O.T.

SLP(C) No. 12512/2025 (XVI)
IA No. 112547/2025 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT, IA No. 112548/2025 - EXEMPTION FROM FILING O.T.

Date : 02-05-2025 These matters were called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE M.M. SUNDRESH
HON'BLE MR. JUSTICE RAJESH BINDAL

For Petitioner(s) Ms. Anitha Shenoy, Sr. Adv.
Mr. Gaurav Agarwal, Sr. Adv.
Ms. Anindita Mitra, AOR
Ms. Ayushma Awasthi, Adv.
Ms. Sadhana Madhavan, Adv.
Mr. Shubhankar Sengupta, Adv.
Ms. Niharika Srivastava, Adv.
Mr. Arush Bhatia, Adv.
Mr. Shubhankar, Adv.

For Respondent(s) :

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Applications for exemption from filing c/c of the impugned judgment and exemption from filing O.T. are allowed.

2

Learned senior counsel appearing for the petitioners submitted that there is absolutely no fault on the part of the petitioners. The petitioners were qualified at the relevant point of time. In any case, subsequent license has been obtained.

It is further submitted that pursuant to the work order issued, the contract has put into operation. The agreement has been entered into the parties.

Issue notice.

Status quo, existing as on today, shall be maintained by the parties.

(SWETA BALODI) (POONAM VAID)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS ASSISTANT REGISTRAR

संबंद्ध किए गए मैनपॉवर एजेंसी की सूचना निगम के पत्रांक–9636, दिनांक–16/02/2024 तथा पत्रांक–10330, दिनांक–28/02/2024 द्वारा राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को प्रेषित की गई, जिसके अनुसार अग्रतर कार्रवाई संबंधित स्वास्थ्य संस्थान द्वारा की जानी है। उपरोक्त के पश्चात् कुछ संस्थाओं द्वारा उनके जिला से संबंद्ध एजेंसी से अनुबंध कर मैनपॉवर की सेवा लेने की कार्रवाई की जा रही है/की गई है। इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय में कई एजेंसीयों द्वारा वाद दायर किया जा रहा है। न्यायालय में दायर वादों के माध्यम से कई मैनपॉवर एजेंसी ने उनके एवं संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के बीच पूर्व में किए गए अनुबंध को निर्वाध रूप से जारी रखने की मांग की है। दायर किए के वाद में कुछ बातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कई जिला संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–10 (7), दिनांक–21/04/2023 के माध्यम से निर्गत दिशा निर्देश की अवहेलना करते हुए पूर्व के अनुबंध को बिना शर्त विस्तारित किया गया है या नया कार्यादेश निर्गत किया गया है। इस पत्र में कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए। इन उदाहरणों से स्पष्ट पुष्टि होती है कि कुछ जिला स्वास्थ्य समिति, सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल तथा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–10(7) दिनांक–21/04/2023 की अवहेलना करते हुए निगम के निविदा के पश्चात् भी पूर्व

ANNEXURE-'I'

INDIRAGANDHI INSTITUTEOF MEDICALSCIENCES
SHEIKHPURA,PATNA-800014

E-Tender Notice No.- 23 /2024-2025/Watch & Ward Services (Unit-B)/IGIMS/Store

The Director, IGIMS, PATNA invites E-tender in Two Bid System (i.e. Technical and Financial Bid) from reputed, experienced and financially sound Security Agencies for Unit- 'B' through online e-procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in.

Sl No.	Brief Description of Service	Qty.	Tender Fee (in Rs.)	Bid Security (in Rs.)
1.	Deployment of Security Agency for providing Watch & Ward Services for Unit-'B' for Two years at IGIMS, Patna & extendable up to another One year on satisfactory performance	Service Contract	Rs. 5,000/-	Rs. 18 Lakhs

Bidders can download complete set of bidding document from e-procurement platform: www.eproc2.bihar.gov.in.
The e-tender notice and Tender documents is also available in our website: **www. igims.org** Bidders have to submit the bids online only by uploading all the required documents through: www.eproc2.bihar.gov.in.

IMPORTANT DATES

Date of publication & downloading of Bid documents	20.01.2025
Last Date of submission of hard copy of documents	19.02.2025
Date of Pre Bid Meeting	25.01.2025
Closing of Bid submission	18.02.2025
Opening of tender bid(Eligibility and technical)	20.02.2025

Sd/-
DIRECTOR
IGIMS, Sheikhpura, Patna-14

13	Pg-27. 12 As per PSARA 2005- License number under Bihar Private Security (Regulation) Rules 2009 issued by Govt. of NCT of Delhi and its date of validity.	License number under Bihar Private Security (Regulation) Rules 2009 issued by Competent authority and its date of validity.
14	ESI not applicable on wages above 21000/- But as per our price break we have calculated ESI.	It should be as per Directorate General of Resettlement (DGR), Ministry of Defence, Govt. of India norms.
15	EPF calculation on ceiling limit of 15000/month which come 1950 @ 13% of 15000. But you have calculated full amount in price Break-up(Salary Break-up)	It should be as per Directorate General of Resettlement (DGR), Ministry of Defence, Govt. of India norms.
16	Minimum Service charges @ 3.85 will be quoted. Rate of equipments (QRT Vehicle, Bikes, towing vehicles, PA systems, walky-talky, DFMD etc. should be separated from Service Charges.	It should include following points:- 1. The above wages will be paid for deployment of actual members of Security Personnel on duty as per adequate proof thereof. The said wages shall be for 26 days for a month of 30 days with 4 (Four) PAID OFFS in a month and 3 (Three) PAID national holiday in a year/compensatory offs in lieu of national holidays on pro rata basis. The minimum wages shall be as per the rates notified by DGR, Ministry of Defence, Office Memorandum No. 28(75)/2020-D (RES-1) dated- June, 2021 (Government of India from time to time). 2. Employee contribution for EPF, ESI, EDLI and Bonus will be reimbursed. 3. Evaluation of financial bids will be based on Service Charges quoted by the bidders in financial bid. 4. The prospective bidders are hereby advised to take into account all provisions like Uniforms, Security management software, Vehicle Tokens, Wireless Sets, Inverted mirrors, Mobile Phones, Vehicles of all types including Quick Response Vehicles including fuels (diesel, petrol etc.), HHMDs, Identity Cards, Salary Slip, Maintenance of Records, Stationery etc. and TDS deduction at source at notified rates from time to time on each bill, prior to quote Service Charges in their offer for all categories of manpower. Prospective bidders are advised to visit the Institute and access the work before submitting the bid. All the Charges to be incurred as stated above in the proposed Service Charge. 5. The Agency will have to provide 2 sets of uniforms per year including I-cards, caps, shoes, belts, gumboots, rain coat etc. free of cost approval by the competent authority of IGIMS, Patna. 6. L1 will not be decided on service charge less than 3.85% (As per Letter No.- M-4-06/2023/2988/B., Govt. of Bihar) and will be treated non-responsive bid if service charge quoted less than 3.85 %. The service charges should not be quoted more than 2 digits after decimal. It will be considered as unresponsive.

5/8/25, 4:19 PM Goods & Services Tax (GST) | Services

Skip to Main Content A+ A-

Goods and Services Tax

Government of India, States and Union Territories

REGISTER LOGIN

Home › Search Taxpayer › Search by GSTIN/UIN

Search Taxpayer • indicates mandatory fields

GSTIN/UIN of the Taxpayer•

Enter GSTIN/UIN of the Taxpayer

SEARCH

Search Result based on GSTIN/UIN : 10AMPPK3347M1ZV

Legal Name of Business	Trade Name	Effective Date of registration
RISHI KAPOOR	M/S F.F INFO-COM	01/07/2017

Constitution of Business	GSTIN / UIN Status	Taxpayer Type
Proprietorship	Active	Regular

https://services.gst.gov.in/services/searchtp 1/5

5/8/25, 4:19 PM Goods & Services Tax (GST) | Services

Administrative Office	Other Office	Principal Place of Business
(JURISDICTION - STATE) State - Bihar Division - Patna East Circle - Patna City West	(JURISDICTION - CENTER) State - CBIC Zone - RANCHI Commissionerate - PATNA I Division - PATNA EAST DIVISION Range - PATNA CITY RANGE	FIFTH FLOOR, THE EAGLE VIEW, SONA GOPALPUR, SAMPATCHAK RAOD, SAMPATCHAK PATNA, Patna, Bihar, 800007

Whether Aadhaar Authenticated?	Whether e-KYC Verified?	Additional Trade Name
Yes (On 23/01/2024)	Not Applicable	View

Nature Of Core Business Activity

Trader - Wholesaler/Distributor

Nature of Business Activities

1. Works Contract2. Wholesale Business

https://services.gst.gov.in/services/searchtp 2/5

से उन जिलों में कार्यरत या दूसरे मैनपॉवर एजेंसी के साथ अनुबंध किया गया। निगम द्वारा न्यायालय में इन वादों के विरुद्ध इस आशय का शपथ पत्र दायर किया जा रहा है कि संबंधित स्वास्थ्य संस्थान/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा विभागीय निर्देश की अवहेलना कर दूसरे मैनपॉवर एजेंसी के साथ अनुबंध किया गया/कार्य आदेश निर्गत किया गया है। इसके लिए संबंधित सिविल सर्जन, अधीक्षक, डीपीएम दोषी हैं, निगम/स्वास्थ्य विभाग की इसमें किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि जो सिविल सर्जन/अधीक्षक/डीपीएम स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-10(7) दिनांक-21/04/2023 के द्वारा निर्गत स्पष्ट निर्देश की अवहेलना कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की कृपा की जाए तथा इस संदर्भ में सभी सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जीएनएम, एएनएम स्कूल आदि को भी विभागीय स्तर पर स्पष्ट निर्देश देने की कृपा की जाए। लेकिन अपर मुख्य सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग के स्तर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे उक्त निविदा को बिना उचित कारण बताएं रद्द कर दिया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना और उक्त आदेश पर स्थगन आदेश दिया। इसके बावजूद भी बिहार के कई संस्था ने अपनी मनमानी जारी रखी।

बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH के सबसे बड़े भ्रष्ट अधीक्षक ने तो कमाल ही कर दिया। जहां पीएमसीएच में मुख्यमंत्री से लेकर बड़े-बड़े अधिकारी और मंत्रियों का रोज आना-जाना लगा रहता है, वही इस आदेश को कूड़ेदान में फेंक दिया गया और बीएमएसआईसीएल द्वारा चयनित एजेंसियों को दरकिनार कर PMCH ने एलिट फाल्कन्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा विस्तार दे दिया, जबकि यह एजेंसी तय मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। इसका टर्नओवर निर्धारित 5 करोड़ के मुकाबले केवल 3 करोड़ था। इसके बावजूद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसे कार्य दे दिया गया। इस मामले को लेकर विभिन्न एजेंसियों ने पटना हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएँ दायर कीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिनांक 2 मई 2025 को SLP संख्या 12510/2025 में बिहार सरकार के आदेश पर स्थगन आदेश (Stay Order) जारी किया। बावजूद इसके PMCH के अधीक्षक ने एलिट फाल्कन्स की सेवा को बरकरार रखा है। सूत्रों की मानें तो इस एजेंसी में अधीक्षक सहित कई उच्च अधिकारी आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं, जिससे इस एजेंसी को बार-बार सेवा विस्तार दिया जा रहा है। PMCH और IGIMS के अधीक्षकों को बार-बार सेवा विस्तार मिलने और नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्त रहने के पीछे राजनीतिक संरक्षण का आरोप भी लगाया जा रहा है। कहा जाता है कि ये अधिकारी खुलेआम दावा करते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास तक को "मैनेज" कर रखा है। यह स्थिति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ईमानदारी की छवि को भी सवालों के घेरे में खड़ा करती है।

पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की निविदा संख्या ज्ञापांक-2935, दिनांक-30/04/2022 में पिछले 3 वर्ष में 2018-19, 19-20, 2020-21 में न्यूनतम 5 करोड़ का औसत टर्नओवर की शर्तें रखी हुई थी, लेकिन मेसर्स एलिट फाल्कन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका 3 वर्ष का औसत टर्नओवर 3 करोड़ भी नहीं था, उसको पीएमसीएच का कार्य आवंटित कर दिया गया। वर्ष 2018 दिसंबर में निबंधित इस एजेंसी का निविदा से पूर्व पिछले तीन वित्तीय वर्ष के औसत टर्नओवर निर्धारित शर्त से अप्रत्याशित कम है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उसके जीएसटी और ROI में दिए गए रिटर्न से प्रमाणित होता है। पहले तो फर्जी कागज के आधार

5/8/25, 4:19 PM Goods & Services Tax (GST) | Services

Dealing In Goods and Services

Goods		Services	
HSN	Description	HSN	Description
49119920	PLAN AND DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL ENGINEERING, INDUSTRIAL, COMMERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR SIMILAR PURPOSES REPRODUCED WITH THE AID OF COMPUTER OR ANY OTHER DEVICES	00440410	WORKS CONTRACT SERVICES
49019100	DICTIONARIES AND ENCYCLOPAEDIAS, AND SERIAL INSTALMENTS THEREOF		

HSN: Harmonized System of Nomenclature of Goods and Services

SHOW FILING TABLE SHOW RETURN FILING FREQUENCY

Financial Year*

2024-2025 SEARCH

Search Result based on GSTIN/UIN : 10AMPPK3347M1ZV

Filing details for GSTR3B

Financial Year	Tax Period	Date of filing
2024-2025	March	21/04/2025
2024-2025	February	21/03/2025
2024-2025	January	20/02/2025
2024-2025	December	22/01/2025
2024-2025	November	20/12/2024
2024-2025	October	20/11/2024
2024-2025	September	18/10/2024
2024-2025	August	19/09/2024
2024-2025	July	22/08/2024

Filing details for GSTR-1/IFF

Financial Year	Tax Period	Date of filing
2024-2025	March	19/04/2025
2024-2025	February	21/03/2025
2024-2025	January	20/02/2025
2024-2025	December	22/01/2025
2024-2025	November	20/12/2024
2024-2025	October	20/11/2024
2024-2025	September	18/10/2024
2024-2025	August	19/09/2024
2024-2025	July	19/08/2024

About GST Website Policies Related Sites Help and Taxpayer Contact Us

https://services.gst.gov.in/services/searchtp

पर कार्य आवंटित कर दिया गया और फिर विभागीय आदेश को नहीं मानते हुए केंद्रीय कृत निविदा में ISI को कार्य नहीं आवंटित कर, मेसर्स एलिट फाल्कन्स प्राइवेट लिमिटेड को कार्य विस्तार दे दिया गया। बिहार सरकार के पत्रांक संख्या-837(12), दिनांक-02/09/2024 के अनुसार बीएमएसआईसीएल के निविदा को रद्द करते हुए एक माह के भीतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया गया, लेकिन यह मामला पटना उच्च न्यायालय से होते हुए अभी सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय में केस संख्या SLP NO.-12510/2025, दिनांक-02/05/2025 के आदेश में न्यायालय ने बिहार सरकार के आदेश संख्या-837(12) दिनांक-02/09/2024 के आदेश पर स्थगन आदेश दे

5/8/25, 4:19 PM Goods & Services Tax (GST) | Services

GST Council Structure

GST History

Website Policy

Terms and Conditions

Hyperlink Policy

Disclaimer

Central Board of Indirect Taxes and Customs

State Tax Websites

National Portal

Facilities

System Requirements

GST Knowledge Portal

GST Media

Site Map

Grievance Nodal Officers

Free Accounting and Billing Services

GST Suvidha Providers

Help Desk Number: 1800-103-4786

Log/Track Your Issue: Grievance Redressal Portal for GST

© 2025-26 Goods and Services Tax Network

Site Last Updated on 29-04-2025

Designed & Developed by GSTN

Site best viewed at 1024 x 768 resolution in Microsoft Edge, Google Chrome 49+, Firefox 45+ and Safari 6+

https://services.gst.gov.in/services/searchtp

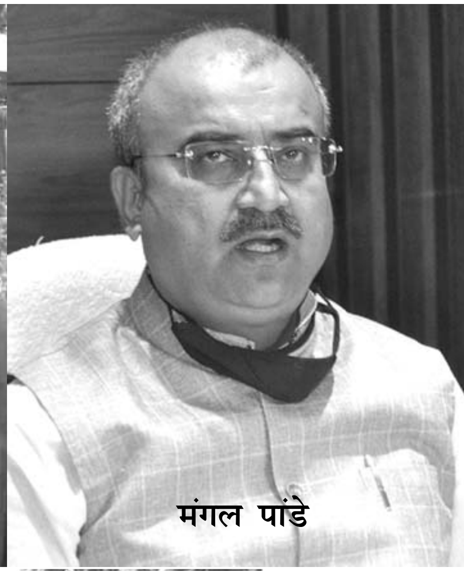

दिया है। बावजूद PMCH के अधीक्षक ने अभी तक एलिट फॉल्कंस प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं बरकरार रखी हैं। सूत्र बताते हैं की एलीट फॉल्कंस प्राइवेट लिमिटेड में PMCH अधीक्षक सहित वरीय अधिकारियों का भी पैसा लगा हुआ है, जिसके कारण अधीक्षक उसकी सेवा विस्तार बार-बार दे रहे हैं। पीएमसीएच के अधीक्षक को दो बार सेवा विस्तार दिया जाना और एलिट टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड का बार-बार सेवा विस्तार दिया जाना सिर्फ भ्रष्टाचार की ओर इशारा नहीं करता है, वरन पीएमसीएच में हो रहे कुकृत को भी दर्शाता है। पीएमसीएच में किसी भी पत्रकार का जाना माना है। जाने पर उसकी पिटाई होती है। कई पत्रकार की पिटाई हो चुकी है। PMCH बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन आज कल यह अय्याशी का अड्डा बना हुआ है। PMCH के अधीक्षक पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और कई नर्स ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि पीएमसीएच के अधीक्षक बालिका सुधार गृह जैसे कांड पीएमसीएच में कर रहे हैं। PMCH को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया गया है। पीएमसीएच के अधीक्षक चाहे जितना भी कुकृत कर लें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्योंकि उनके कुकृत में अधिकारी से लेकर बड़े-बड़े मंत्री तक शामिल हैं। वहां कार्य कर रहे एलएनटी के अधिकारी और कर्मचारी कहते हैं कि PMCH की गरिमा को ताख पर रखकर अधीक्षक ने इसे अय्याशी और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है।

PMCH में पत्रकारों पर हमला होना, महिला कर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाना और अधीक्षक पर 'बालिका सुधार गृह' जैसी घटनाओं में लिप्त होने के आरोप एक गंभीर चिंता का विषय हैं। कई नर्सों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि अधीक्षक की कार्यशैली शर्मनाक है और वह संस्थान को भ्रष्टाचार और अय्याशी का अड्डा बना चुके हैं। बिहार के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में इस प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार और शक्ति का दुरुपयोग न केवल राज्य की छवि को धूमिल करता है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी खतरे में डालता है। निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो यह भ्रष्टाचार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भयावह उदाहरण बन जाएगा। ●

अपराध नियंत्रण के लिए फाइल नहीं फील्ड पुलिस की है जरूरत!

● अमित कुमार

जय हिंद! ये दो शब्दों का मिलन दिल को छू देने वाला, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध कराने वाला, देश के लिए मर मिटने वाला अहसास कराता है. प्राय: ये शब्द सेना और पुलिस महकमे के जवानों के मुख से सुनने को मिल जायेंगे. उस वीर जवानों के अहमियत को समझना होगा. ये बात क्यों कही जा रही है, यह आगे स्पष्ट हो जायेगा.

बहरहाल, देश का बहुचर्चित राज्य बिहार इन दिनों पुराने जंगल राज के याद को ताजा कर रहा है. अपराधी बेलगाम हैं तो वही पुलिस को ट्रैफिक चलान काटने और शराब पकड़ने जैसा कठोर काम सौंपा गया है! बेलगाम अपराधियों को पकड़ने जाती पुलिस को भी अपराधी कुछ नहीं समझ रहे, नतिजतन पुलिस पर हमले हो रहे हैं. हालांकि इस मामले में आलाधिकारी ने कठोर कदम उठाते हुए एनकाउंटर किये जाने का आदेश दिया और हुआ भी ऐसा. किंतु अपराधी अपराध कर ही रहे हैं. कारण है, जिस पुलिस का अपराधियों में खौफ है, जिसका सूचना तंत्र मजबूत है, जो अपराध होने की भनक को पहले ही भांप लेता है; उससे कलर्कियल काम कराया जा रहा है. उनकी सेवा अपराधियों पर लगाम कसने के लिए लेनी चाहिए. दुखद है की वह फाइलों में सिमटे हुए हैं या फिर सिपाही बहाली जैसे अन्य कार्यों में. मैं ये नहीं कह रहा की ये काम गलत है और इस कार्य को भी कोई पुलिस कर्मी ही करेगा, पर जिस पुलिस कर्मी की जहाँ जरूरत होनी चाहिए वह वहाँ नहीं है.

गौरतलब है की राघव दयाल 1994 बैच के प्रमोटिव पुलिस उपाधिक्षक हैं, जो अभी बिहार विशेष सशत्र पुलिस, जमुई में पुलिस उपाधिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. बता दें कि पुलिस उपाधीक्षक की पहला कार्य सेवा उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) में दिया। विशेष अभियान में उनके कार्यों के बदौलत कुछ वर्षो में राघव को अनुमंडल पुलिस पधाधिकारी हाजीपुर, सदर बनाया गया। वैशाली जिले का हाजीपुर क्षेत्र शहरी और ग्रामीण होने के कारण इन जगहों पर उन्होंने चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाकर अपराध पर अंकुश लगाने का काम किया। आज राघव दयाल हाजीपुर में कार्यरत्त नहीं हैं किन्तु वहां की जनता उनके कार्यों को याद करती है। बता दें कि हाजीपुर के बाद उनका तबादला नगर पुलिस उपाधीक्षक मुजफ्फरपुर किया गया। मिनी राजधानी के नाम से जाने पहचान रखने वाला मुजफ्फरपुर पूरे तरह से पॉश एरिया माना जाता है। रसूकदारों और सुविधाओं से लैश मुजफ्फरपुर नगर में कार्य करना बड़ी चुनौती होती है। बहरहाल, राघव दयाल को यहां का नगर पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया। इसके बाद उनका तबादला बिहार विशेष सशत्र पुलिस, जमुई के उपाधीक्षक के पद पर किया गया, जो अभी तक यहां अपनी सेवा दे रहे हैं।

बता दें कि तेज तर्रार और कुशल सूचना तंत्र के बदोलत राघव दयाल कई संगीन अपराधी को जेल भेज चुके हैं. वही अपराधियों में जितना उनके नाम का खौफ है, उससे ज्यादा जनप्रिय रहे हैं। यही कारण है की जहाँ भी वह कार्य किये वहाँ के लोगों के प्रिय रहे हैं। विडम्बना है की ऐसे दिलेर पुलिस उपाधीक्षक को उनके वास्तविक कार्य से दूर रखा गया है। वे कई वर्षो से बिहार विशेष सशत्र पुलिस, जमुई में वह अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे पुलिस कर्मी को अपराध पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी बिहार के सुपरकॉप विनय कुमार जो पुलिस महानिदेशक बिहार हैं, उन्हे देते हैं तो निश्चित ही अपराध नियंत्रण का परिणाम उम्मीद से बढकर होगा।●

गुप्तेश्वर जी महाराज का मसौढ़ी में श्रीराम कथा का भव्य आयोजन

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

पटना जिला के मसौढ़ी गांधी मैदान में श्रीराम कथा का भव्य आयोजन कथा व्यास 'जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री गोविन्दाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज' के मुखारविंद से 12 मई से 18 मई 2025 तक शाम 7 बजे से 10 बजे तक किया जा रहा है। श्री गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज बिहार के बहुत ही चर्चित डीजीपी भी रहे हैं। डीजीपी के कार्यकाल में भी इन्होंने ही अनगिनत कार्य ऐसे किए, जिससे गुप्तेश्वर जी महाराज का नाम बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के पटल पर रखकर आज भी चर्चा किया जाता है। बिहार के डीजीपी से सेवानिवृत होने के बाद इन्होंने 48 देशों में सनातन धर्म का अलख जलाने वाले महाराज जी मसौढ़ी में भी अपना अलख जगा रहे हैं। हजारों भक्तों एवं श्रद्धालुओं को भक्ति मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करने की चर्चा अपने कथा में कर रहे हैं। इस कथा का भव्य आयोजन, मसौढ़ी की जनता के लिए किया गया है। इस आयोजन के प्रमुख भूमिका में राहुल सर, विद्या एजुकेशनल ग्रुप के डॉ. सुनील भावस्कर, जदयू नेत्री खुशबू रानी, डॉ. सुधीर कुमार, अधिवक्ता चंद्रकेत सिंह चंदेल एवं महेन्द्र सिंह अशोक, कृष्णा सर, अमित जी, मिठ्ठू जी सहित अन्य गणमान्य लोग महाराज जी के सेवा में जुटे रहे।●

प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के छात्रों ने लहराया परचम

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

मसौढ़ी में पी.पी. पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने एक बार पुन: अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाते हुए अपने प्रतिभा को दिखाकर सी.बी.एस.ई. की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में अपना परचम लहराया है। विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि इस स्कूल के 12वीं में सागर गुप्ता ने 94%, हर्ष कुमार ने 92.6%, अंशिका कुमारी ने 92%, अनामिका कुमारी 91.6% एवं सुहानी कुमारी ने 90% अंक प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन करके सभी को गौरवान्वित किया है। वहीं 10वीं की परीक्षा में सोनम कुमारी ने 95.4%, हर्ष शर्मा ने 93.2% एवं राहुल कुमार ने 92.4% अंक प्राप्त किए हैं। पी.पी. शैक्षणिक समूह के चेयरमैन डॉ० अभिराम शर्मा ने इस परीक्षा का श्रेय छात्र-छात्राओं, विद्यालय के शिक्षकों एवं अभिभावकों को दिया है। इस स्कूल के 25 (पच्चीस) विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर अंक लाकर अपने स्कूल का सम्मान व प्रतिष्ठा को काफी बढ़ाया है। इस स्कूल में सातवां स्थान प्राप्त करने वाले में रविशंकर कुमार एवं श्रेया कुमारी हैं। वैसे ही तीसरा स्थान पर राहुल कुमार और प्रियांशु राज हैं। चौथा स्थान पर निशांत कुमार और अभिषेक राज हैं, जिन्होंने 92.2% अंक प्राप्त किया है। सातवाँ स्थान पर दोनों विद्यार्थियों ने 91.4% अंक प्राप्त किए हैं।●

अंतर्जातीय विवाह में नौकरी की मांग को लेकर दिया गया धरना

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

प्रखंड कार्यालय फतुहा में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया जिसका अध्यक्षता राजद के रामजतन यादव, मुख्य अतिथि भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल। जदयू के वरिष्ठ नेता मुन्ना कुमार यादव, इस आयोजन में कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई है। मांगों में अंतर्जातीय शादी करने पर सरकारी नौकरी दी जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऐसी मुंद्रा योजना की शुरुआत की गई है कि बगैर सिक्यूरिटी एवं गवाह के 20 लाख रुपए तक बहुत कम सूद पर ऋण देने का प्रावधान है,इस पैसे से अपने के अलावा भी कुछ लोगों को बेरोजगारी भी दूर कर सकते हैं। बताया जाता है कि बैंक द्वारा नहीं किसी बेरोजगारों को दी गई है, नहीं कोई गरीब कार्यकर्ता को दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के बैंक प्रबंधक अपने परिवार और वेवशायी को दी गई है।

स्कूलों में छात्रों को नामांकन के लिए लिए उम्र प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के लिए परेशानी की जा रही है। बच्चों का जन्म का समय माता-पिता एवं पड़ोसी से ज्यादा कौन जानता है।कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट से लिखवाकर कर लाना होगा। छ फार्म भरवाया जाता है। पांच गवाह के साथ सबों का आधार कार्ड जमा ली जाती है। बताया जाता है कि यह सब परेशानी कर दो तीन हजार रुपए खर्च करवाया जा रहा। उम्र प्रमाण पत्र के लिए माता पिता ही काफी है तथा उम्र का अनुमान लगाना शिक्षक ही काफी है, शदियों से यही परंपरा चलती आ रही है। यह परेशानी करना बंद करें। इस अवसर पर भाजपा नगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, संजय कुमार, इंद्र देव मिस्त्री, विजय प्रसाद विमल यादव, संतोष यादव, आयुष कुमार, प्रिंस कुमार, मनीषा कुमारी, प्रेम कुमार, संजय दास, संजय यादव, अजय कुमार, राम कुमार, अजीत कुमार, मुकेश कुमार, हरी मिस्त्री, डॉक्टर विनय कुमार आदि।●

फतुहा की आन-बान-शान बने टुनटुन यादव

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

टुनटुन यादव बने फतुहा का आन-बान-शान। टुनटुन जी का एक ही नशा है कि फतुहा के विकास का गति को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले अपने जुझारू पत्नी रुपा देवी को का राजनीति में लाए। रुपा ने अपनी व्यवहार से फतुहा वासियों का दिल ऐसा जीत लिया कि फतुहा वासियों ने नगर परिषद के कुर्सी पर बैठा दिया। रुपा बेटी ने अपने पति टुन टुन यादव को अपना प्रतिनिधि भी बना दिया। टुनटुन यादव ने प्रतिनिधि बनकर फतुहा वासियों का सपना पुरा करने में लगे हुए हैं। समुचे फतुहा में बिजली से जगमगा दिया, आज समुचे फतुहा कैमरा के नजरों में है। शहरों में आवश्यकता के अनुसार सड़क के किनारे जल की व्यवस्था, वार्ड नंबर 27 में पार्क बना दिया, नली गली का निर्माण, समय समय पर नालों का सफाई, महारानी चौक पर टेम्पू स्टैंड, आवश्यकता के अनुसार शौचालय का भी निर्माण किया गया। सड़कों पर कई स्थानों पर टीबी के बाद, फोर लाईन ओवरब्रिज के पास क्लब रेस्टुरेंट व उत्सव हॉल निर्माण कार्य किया गया है। क्लब सचमुच

सपनों का महल है। इसका उद्घाटन बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री पशुपति पारस कुमार व पूर्व मंत्री श्याम रजक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर पटना मेयर सीता साहू, विधान पार्षद नागेंद्र कुमार यादव, बिहान पार्षद नवल किशोर यादव, नगर प्रमुख रूपा कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार यादव, संतोष कुमार चंद्रवंशी, लोजपा के रंजीत कुमार यादव, फतुहा भाजपा के नगर अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी,भाजपा फतुहा नगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, सुनील कुमार बर्मा। ऐसे उत्कृष्ट कार्यो के लिए मैं डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल रुपा बेटी, टुनटुन यादव जी को अपने पुरे परिवार की ओर से बधाई देता हूं कि जनता के सपनों का साकार करते रहे। जदयू के वरिष्ठ नेता मुन्ना कुमार यादव ने भी फतुहा नगर परिषद के अध्यक्ष रुपा देवी एवं प्रतिनिधि टुनटुन यादव को ऐसे उत्कृष्ट कार्यो के लिए बधाई दी।●